संयम ◆संस्कार ◆संतुलन

R.N.I. No.-UPHIN/2004/22466

वर्ष-22 अंक- 159
पृष्ठ 8
शुक्रवार
27 फरवरी 2026
प्रातः संस्करण
हिन्दी दैनिक
प्रयागराज
मूल्य-1.00

शहर समता

प्रयागराज से प्रकाशित Email : shaharsamta@gmail.com Website : https://Shaharsamta.com

सम्पादक-उमेश चन्द्र श्रीवास्तव

विविध- सूट की स्लीव्स चौड़ी होने पर टेलर..

विचार- वर्चस्व को नकारना भारतीय संघ...

खेल- अर्श से फर्श पर श्रीलंका क्रिकेट...

रोड शो में योगी ने दिया निवेश का आमंत्रण

यूपी और यामानाशी के बीच सहयोग भारत-जापान संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाएगा : मुख्यमंत्री

लखनऊ,संवाददाता। जापान दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और बड़ी सफलता हासिल की है। यूपी सरकार ने जापान के यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारतीय छात्रों को जापान में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यामानाशी में आयोजित यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो में प्रदेश की नई विकास नीति और निवेश संभावनाओं को वैश्विक उद्योग जगत के सामने प्रमुखता से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने शासन की कार्यशैली रिएक्टिव से बदलकर प्रोएक्टिव बनाया है। यही परिवर्तन आज प्रदेश की तेज आर्थिक प्रगति का आधार बना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश व यामानाशी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर

हुए हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थानों के छात्र जापान में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और इस तकनीक को प्रदेश की इंडस्ट्रीपब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा क्षेत्र में लागू किया जाएगा। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में कई जी 2जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और जी 2बी गवर्नमेंट टू बिजनेस स्तर की बैठकों में भाग लिया, जहां भारतीय दूतावास के सहयोग से जापानी उद्योग समूहों से व्यापक संवाद हुआ। उन्होंने यामानाशी प्रशासन को सक्रिय पहल कर निवेश संवाद को आगे बढ़ाने के लिए विशेष धन्यवाद दिया।मुख्यमंत्री ने रोबोटिक्स को भविष्य की प्रमुख तकनीक बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में रोबोटिक्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की व्यवस्था की है। 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां प्रकृति की विशेष कृपा है। भारत की सबसे उर्वर भूमि, सर्वाधिक जल संसाधन, विशाल मानव संसाधन और आध्यात्मिक–सांस्कृतिक विरासत उत्तर प्रदेश को विशेष पहचान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है और पिछले नौ वर्षों में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय तथा अर्थव्यवस्था तीन गुना करने में सफलता मिली है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन व्यवस्था में आए परिवर्तन का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले समस्याओं पर प्रतिक्रिया देने वाली व्यवस्था थी, जबकि अब उत्तर प्रदेश ने प्रोएक्टिव गवर्नेंस मॉडल अपनाया है। निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को सुविधा देने, नई तकनीक अपनाने और वैश्विक साझेदारी बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार पहल कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी प्रांत के राज्यपाल एवं उनकी टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जापान सरकार और यामानाशी प्रशासन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को उनके विशिष्ट क्षेत्रों को नजदीक से समझने और उद्योग जगत से सीधे संवाद का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है।

प्रधानमंत्री मोदी बोले-

यहां आना मेरे लिए गर्व और भावुकता का पल

तेल अवीव,एजेंसी। पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण ने इस्राइली संसद को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। उनके भाषण को लेकर इस्राइल के प्रधानमंत्री बेनजामिन नेतन्याहू ने कहा, कल आपके नेसेट में प्रेरक भाषण के बाद इस्राइल में कोई भी आंख सूखी नहीं रही। नेतन्याहू ने मोदी के दो दिन के दौरे को श्संक्षिप्त लेकिन अत्यंत फलदायक और अत्यंत भावुकश बताया। उन्होंने कहा, यह एक अद्भुत दौरा रहा। अद्भुत निष्कर्ष और अद्भुत अनुभव रहे। इसके बाद हमें न केवल अपने दिलों में गहराई से झांकने का अवसर मिला, बल्कि हमारे दोनों देशों के अद्भुत मस्तिष्कों को भी समझने का मौका मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की सोच स्पष्ट है– ह्यूमैनिटी मस्ट नेवर बिकम अ विक्टिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट (मानवता को कभी भी संघर्ष का शिकार नहीं बनना चाहिए)। गाजा शांति पहल से शांति का एक रास्ता बना है। भारत ने भी इन प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया है। भविष्य में भी हम सभी देशों के साथ हम संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, आपकी आत्मीयता और गर्मजोशी ने मेरी यात्रा को यादगार बना दिया है। आप सभी लोगों से जो प्यार मिला है, उसके लिए आप सभी को बहुत–बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। इस्राइली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि इनोवेटर्स को जोड़ना हमारी मुख्य प्राथमिकता रही है। भारत इस्राइल यूएई और अमेरिका के साथ नई गति के साथ आगे बढ़ेंगे। भारत–इस्राइल एक साथ संकल्पित हैं कि हम आतंकवाद का विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। पश्चिम एशिया में शांति और अस्थिरता से भारत के सीधे सुरक्षा हित जुड़े हैं। इसीलिए हमने शुरुआत से ही संवाद और शांतिपूर्ण ढंग का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग तकनीकी साझेदारी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे एआई, क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग को नई गति मिलेगी। इस्राइल में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। रक्षा के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। पिछले वर्ष हुए समझौतों से इसमें नए आयाम जुड़ेंगे। हम मिलकर जॉइन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके लावा सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस में भी हम कदम आगे बढ़ाएंगे। दोनों देश अब कृषि को भी फ्यूचरिस्टिक दिशा देने जा रहे हैं।

राहुल ने सरकार को ट्रेड डील पर घेरा

किसान की सुरक्षा-सम्मान से ही भारत सफल होगा

कन्नूर,एजेंसी। केरल दौरे पर पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत–अमेरिका व्यापार समझौते पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। कन्नूर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत तभी सफल हो सकता है जब हमारे किसानों का सम्मान और सुरक्षा हो। इतना ही नहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एपस्टीन फाइलों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकाने के लिए किया ताकि वे एक ऐसे व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करें जिससे भारतीय किसानों की बलि चढ़ जाएगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता कन्नूर जिले के पेरावूर में किसानों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार इस सरल तथ्य को नहीं समझती कि किसान भारत की नींव हैं। उन्होंने कहा कि आईटी और अन्य क्षेत्रों के बारे में लंबे–लंबे व्याख्यान दिए जाते हैं, लेकिन

नींव को मजबूत किए बिना कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है।

उन्होंने कहा, यदि आप नींव का सम्मान नहीं करते, तो कुछ भी नहीं बन सकता। नींव बनाने वाले को सम्मान या सुरक्षा नहीं मिलती। हम हर दिन भोजन करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उसे हमारे खाने की मेज पर कौन रखता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एक ऐसा समझौता किया, जो नींव खोदने जैसा था। उन्होंने कहा, भारतीय किसान छोटे किसान हैं और उनमें मशीनीकरण का स्तर कम है। अमेरिकी किसानों के पास विशाल खेत हैं और उनमें मशीनीकरण का स्तर उच्च है। अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करना एक आपराधिक कृत्य है।" कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पहले के किसी भी प्रधानमंत्री ने अमेरिकी किसानों को भारत में सोयाबीन, सब्जियां और फल जैसे उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा, इससे भारतीय कृषि की नींव नष्ट हो जाएगी। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति किसानों के लिए ही हुई थी। राहुल गांधी ने कहा कि कृषि संबंधी मतभेदों के कारण भारत–अमेरिका समझौता चार महीने से रुका हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया, भारतीय सरकार अमेरिकी कंपनियों के लिए कृषि क्षेत्र खोलना नहीं चाहती थी। कुछ भी प्रगति नहीं हो रही थी और अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे थे। उन्होंने आगे दावा किया कि राष्ट्रपति के संबोधन के बाद उन्हें संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वे दो मुद्दे उठाना चाहते थे। उन्होंने कहा, एक मुद्दा एपस्टीन की उन 35 लाख फाइलों से संबंधित था।

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी से कहा-

माफी काफी नहीं, हार्ड कॉपी वापस लें, डिजिटल कॉपी हटाएं

नई दिल्ली,एजेंसी। एनसीईआरटी की आठवीं कक्षा की किताब के विवादित अंश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान एनसीईआरटी की आठवीं की उस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाला हिस्सा है। किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले अंश को लेकर उपजे विवाद पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में एनसीईआरटी का माफी मांगना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी किताब बच्चों तक जाने देना गलत होगा। न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखना जरूरी है। शिक्षा सचिव और एनसीईआरटी को नोटिस जारी करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जब तक कोर्ट संतुष्ट नहीं हो जाता, सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस किताब की सभी कॉपियों को जब्त करने का आदेश दिया है और साथ ही इसके डिजिटल प्रिंट को भी हटाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर उसके इस आदेश के पालन में कोताही बरती गई तो गंभीर कार्रवाई की जाएगी। सर्वोच्च अदालत ने एनसीईआरटी के निदेशक, स्कूली शिक्षा सचिव को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है और ये पूछा है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया कृत्य लगता है।

सुनवाई के दौरान एनसीईआरटी ने कहा कि वे बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं। किताब से विवादित अंश को भी हटा दिया जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि केवल माफी मांगना और किताब से आपत्तिजनक अंशों को हटाना पर्याप्त नहीं है। एनसीईआरटी के निदेशक को कारण बताना होगा। ये सोच–समझकर उठाया गया कदम है। अदालत ने सवाल किया कि इस मामले को अवमानना क्यों न माना जाए? अदालत ने कहा कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे लोगों का न्यायपालिका में विश्वास कमजोर होगा। किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीईआरटी ने बुधवार को जो जवाब दिया है, उसमें एक भी शब्द माफी वाला नहीं है और इसके बजाय वे इसे सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सीजेआई ने जताई नाराजगी, कहा– किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं गौरतलब है कि बुधवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी ने सीजेआई के सामने यह मामला उठाया था। इसके बाद, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीईआरटी किताब में श्न्यायपालिका में भ्रष्टाचारश चौप्टर पर कड़ी नाराजगी जताई। सीजेआई ने कहा कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने

की इजाजत नहीं दी जाएगी।

नाराजगी जाहिर करते हुए सीजेआई ने कहा, संस्था का प्रमुख होने के नाते मैंने हमेशा अपने दायित्व को निभाया है। मैं किसी को इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो न्यायपालिका को बदनाम करें। किसी कीमत पर मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो। कानून अपना काम करेगा। मैं जानता हूं कि इससे कैसे निपटा जाए। मैं स्वतः संज्ञान ले रहा हूं। दरअसल, एनसीईआरटी ने 24 फरवरी को कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई किताब जारी की, लेकिन किताब के एक अध्याय में श्न्यायपालिका में भ्रष्टाचारश का एक सेक्शन था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद एनसीईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) ने माफी मांगी है और विवादित चैप्टर वाली कक्षा 8 की किताब के वितरण पर रोक लगाई है। मामला सामने आने के बाद स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने तुरंत निर्देश दिया कि अगली सूचना तक इस किताब का वितरण रोक दिया जाए। एनसीईआरटी ने आदेश मानते हुए किताब की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। एक बयान में एनसीईआरटी ने माना कि गलती अनजाने में हुई है। किसी भी संस्था की गरिमा कम करने का कोई इरादा नहीं था। अब इस अध्याय को दोबारा लिखा जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों से सलाह ली जाएगी।

अश्विनी वैष्णव ने सूचनाओं के सत्यापन पर दिया जोर, कहा-

मानव समाज भरोसे की संस्थाओं पर टिका

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत के शीर्ष प्रकाशक समूहों की डिजिटल इकाइयों के संगठन डीएनपीए द्वारा डीएनपीए कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन गुरुवार को किया गया। डिजिटल मीडिया के दौर में समाचार माध्यमों की भूमिका कैसी हो? इस विषय पर यहां विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूरी दुनिया के मीडिया जगत के लिए यह महत्वपूर्ण दौर है। यह सही निर्णय लेने का समय

है। यह जरूरी है कि आम सहमति बने, अच्छे विकल्प सामने आएं और अच्छी सिफारिशें मिलें ताकि भविष्य की नीतियों को आकार दिया जा सके। बदलते दौर में समाचार माध्यमों की भूमिका पर केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि पूरा मानव समाज भरोसे की संस्थाओं पर टिका है। यह भरोसा परिवार से शुरू होता है और सामाजिक पहचान, न्यायपालिका, मीडिया, विधायिका जैसी संस्थाओं तक जाता है। समाज के अलग–अलग अंग और संस्थाएं विश्वास के सिद्धांत पर काम करती हैं। मीडिया घरानों के लिए भी बुनियादी सिद्धांत यही रहता है कि वह निष्पक्ष और जिम्मेदार रहें। मीडिया के समक्ष खतरे भी मौजूद हैं। जैसे– डीप फेक, गलत सूचनाओं का प्रवाह। हर समाज इस तरह के खतरों से जूझ रहा है। जो संस्थाएं शताब्दियों से मौजूद हैं, उन्हें इन खतरों से कैसे बचाए रखा जाए, यह बड़ी चुनौती है। ऑनलाइन सेफ्टी इसके लिए बहुत जरूरी है। खबरों की प्रामाणिकता, बच्चों की सुरक्षा, सिंथेटिक कंटेंट से बचाव भी जरूरी है और इसके लिए निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। वैष्णव ने कहा कि उदाहरण के लिए ग्राहक का होटल प्रबंधन सत्यापन करता है, उसी तरह ऑनलाइन मंचों को भी सत्यापन का ध्यान रखना होगा ताकि कंटेंट का इस्तेमाल करने वालों को किसी तरह का नुकसान न हो।

न्यायपालिका का अपमान करने की कोई मंशा नहीं-शिक्षा मंत्री

नई दिल्ली,एजेंसी। एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका से जुड़े कथित विवादित अध्याय को लेकर देश में उठे राजनीतिक और न्यायिक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि जो कुछ हुआ उससे उन्हें गहरा दुख है और सरकार या शिक्षा मंत्रालय की ओर से न्यायपालिका का अपमान करने की कोई मंशा नहीं थी।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई भी होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार न्यायपालिका का सर्वोच्च सम्मान करती है और किसी भी शैक्षणिक सामग्री के जरिए संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ी सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया की जांच की जा रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि अध्याय तैयार करने में शामिल लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य जागरूकता फैलाना है, संस्थाओं

को बदनाम करना नहीं। यह मामला एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब से जुड़ा है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित एक हिस्सा शामिल किया गया था। इस सामग्री को लेकर वरिष्ठ वकीलों और कई कानूनी विशेषज्ञों ने आपत्ति जताई थी।

मामा के साथ वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे भांजे की सड़क हादसे में मौत, नैनी जेल के सामने हुआ हादसा

प्रयागराज। मामा के साथ बाइक से वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे भांजे की बुधवार रात केंदीय कारागार नैनी के सामने ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं घटना में मामा भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामा के साथ बाइक से वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे भांजे की बुधवार रात केंदीय कारागार नैनी के सामने ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं घटना में मामा भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। अभी तीन दिन पहले ही बीते सोमवार को उक्त स्थान पर ट्रक की चपेट में आने से कक्षा 2 की छात्रा फलीशा की मौत हो गई थी।

मेजा थाना क्षेत्र के ऊंचडीह निवासी अमन शुक्ला (26) पुत्र अखिलेश कुमार शुक्ला बुधवार शाम अपने मामा राजेश त्रिपाठी निवासी संगम विहार कॉलोनी नैनी के साथ एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नैनी गया था। देर रात दोनों एक ही बाइक में वापस संगम विहार कॉलोनी की ओर लौट रहे थे। जैसे ही उन्होंने केंद्रीय कारागार नैनी गेट के सामने से अपनी बाइक टर्न की तभी मिर्जापुर रोड की ओर जा रही है ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया।

दुर्घटना में अमन शुक्ला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मामा राजेश त्रिपाठी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक अमन शुक्ला दो भाइयों में छोटा था। उसके पिता खेती किसानी का काम करते हैं। घटना जिस स्थान पर हुई है वहीं पर बीते सोमवार को ट्रक की चपेट में आने से कक्षा दो की छात्रा फलीशा की मौत हो गई थी। घटना के बाद भी लोगों ने जेल रोड चौकी के सामने से डिवाइड हटाने की मांग की थी, लेकिन अभी तक चौकी के सामने से डिवाइड नहीं हटाया जा सका है।

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पदों की संख्या में संशोधन, अब 7201 पदों पर होगी भर्ती

प्रयागराज। एसएससी ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पुरुष एवं महिला परीक्षा–2025 के लिए भारतीयों की संशोधित संख्या जारी कर दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से रिपोर्ट की गई संशोधित स्थिति के अनुसार, अब 7201 पदों पर भर्ती की जाएगी। एसएससी ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल

(एग्जीक्यूटिव) पुरुष एवं महिला परीक्षा–2025 के लिए भारतीयों की संशोधित संख्या जारी कर दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से रिपोर्ट की गई संशोधित स्थिति के अनुसार, अब 7201 पदों पर भर्ती की जाएगी। पुरुष कांस्टेबल के 4825 पद हैं, जिनमें सामान्य के 1925, ओबीसी के 1065, एससी के 929, ईडब्ल्यूएस के 482 और एसटी के 424 पद शामिल हैं। वहीं, महिला कांस्टेबल के 2376 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 948 ओबीसी के लिए 525, ईडब्ल्यूएस के 238 एसटी के 208 और एससी के 457 पद शामिल है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 22 सितंबर 2025 को प्रकाशित नोटिस की अन्य सभी शर्तें और नियम यथावत रहेंगे।

पटाखा कारोबारी कादिर की बेनामी संपत्ति की जानकारी दें आयकर आयुक्त, 16 मार्च को होगी अगली सुनवाई

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 100 करोड़ की ठगी के आरोपी और चर्चित पटाखा कारोबारी मोहम्मद कादिर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 100 करोड़ की ठगी के आरोपी और चर्चित पटाखा कारोबारी मोहम्मद कादिर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने मुख्य आयकर आयुक्त से विवेचना में देने के साथ ही आरोपियों के बैंक खातों व आय से जुड़ी सभी जानकारियां पुलिस को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की

एकल पीठ ने कादिर को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है।

बुधवार को सुनवाई के दौरान विवेचक ने खुलासा किया कि ठगी की रकम से कादिर ने करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्तियां खड़ी की हैं, जिसमें उसकी पत्नी के नाम खरीदी गईं 10 दुकानें भी शामिल हैं। खाते की जानकारी नहीं मिलने से विवेचना में दिक्कत हो रही है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। मामला प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि कादिर और उसके करीबियों ने ई–टेक्नोक्रेट्स जैसी कंपनियों के जरिये निवेशकों को पैसा दोगुना करने का झांसा दिया था।

विवेचक आजाद कुमार ने कोर्ट को बताया कि निवेशकों के रुपये से आरोपी ने बेहिसाब संपत्ति खरीदी है। हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को अगली सुनवाई तक मनी ट्रेल और संपत्तियों के विवरण की जांच पूरी करने का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को नियत की है। अगली सुनवाई में विवेचक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा।

सरकार बताए– बंदरों के बढ़ते उत्पात को रोकने के लिए जिलों में क्या कार्ययोजना है

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रीसस मकाक (लाल बंदर) के बढ़ते उत्पात को रोकने के लिए राज्य सरकार से कार्ययोजना मांगी है। कहा है कि अगली सुनवाई पर छह अप्रैल तक गाजियाबाद और मथुरा में की गई कार्रवाई का शपथपत्र के साथ विस्तृत रिपोर्ट दें।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रीसस मकाक (लाल बंदर) के बढ़ते उत्पात को रोकने के लिए राज्य सरकार से कार्ययोजना मांगी है। कहा है कि अगली सुनवाई पर छह अप्रैल तक गाजियाबाद और मथुरा में की गई कार्रवाई का शपथपत्र के साथ विस्तृत रिपोर्ट दें। साथ ही इनके उत्पात को नियंत्रित करने के लिए जिलों में अपनाए गए उपायों की भी जानकारी दें।

यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति कुनाल रवि सिंह की खंडपीठ ने विनीत शर्मा व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई

करते हुए दिया है। अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि प्रदेश में रीसस मकाक की वास्तविक संख्या, उनके हॉटस्पॉट क्षेत्रों और मानव–बंदर संघर्ष की प्रकृति को समझने के लिए व्यवस्थित फील्ड सर्वे आवश्यक है।

समग्र कार्ययोजना तैयार करने में कम से कम एक साल का वक्त लगेगा। तब तक बंदरों की पकड़, परिवहन और पुनर्वास से संबंधित वर्तमान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एक हाई पावर कमेटी भी गठित की जा चुकी है।

कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावित अध्ययन से पहले यह स्पष्ट किया जाए कि मौजूदा एसओपी के तहत जिला स्तरीय समितियों ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं।

रामबाग स्टेशन की तीनों लिफ्ट बनी शोपीस, प्लेटफार्म पर शेड नहीं, सिर्फ कागजों पर दुरुस्त हैं सुविधा

प्रयागराज। महाकुंभ मेले के पहले प्रयागराज रामबाग स्टेशन की तस्वीर पूरी तरह से बदली गई पर यहां तमाम समस्याएं अब भी बरकरार हैं। लिफ्ट सजावट की वस्तु बनकर रह गई है। स्टेशन के फुट ओवरब्रिज पर चढ़ने के लिए सभी प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट तो लगाई गई हैं, लेकिन ये अक्सर बंद रहती हैं।

महाकुंभ मेले के पहले प्रयागराज रामबाग स्टेशन की तस्वीर पूरी तरह से बदली गई पर यहां तमाम समस्याएं अब भी बरकरार हैं। लिफ्ट सजावट की वस्तु बनकर रह गई है। स्टेशन के फुट ओवरब्रिज पर चढ़ने के लिए सभी प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट तो लगाई गई हैं, लेकिन ये अक्सर बंद रहती हैं। बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को भारी सामान लेकर सीढ़ियां चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। जिस कायाकल्प का शोर मचा था, उसकी हकीकत यह है कि नवनिर्मित फुट ओवरब्रिज की सीढ़ियों पर लगे ग्रेनाइट पत्थर टूटने लगे हैं। मलाकराज साइड स्थित प्लेटफॉर्म–सात पर बाउंड्री नहीं बन सकी। यहां शेड लगाकर घेरा किया गया है।

इसी तरह रामबाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म–4 की बात करें तो यहां शेड का नामोनिशान नहीं है। इससे यात्री खुले आसमान के नीचे खड़े होने के लिए मजबूर रहते हैं। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल माघ मेले में ही होता है। इतना ही नहीं, इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बहुत कम है। वहीं, प्लेटफॉर्म–7 की बात करें तो इसका भी अधिकांश हिस्सा खुला है। दैनिक यात्री मनोज पांडेय का कहना है कि स्टेशन पर लिफ्ट और अन्य आधुनिक सुविधाएं केवल कागजों पर ही दुरुस्त हैं।

अप और डाउन की 37 ट्रेनों का नहीं है स्टेशन पर ठहराव, दोपहर में सन्नाटा

शहर के बीच में होने के बावजूद रामबाग स्टेशन उपेक्षा का शिकार है। यहां से गुजरने वाली अप और डाउन की 37 ट्रेनों का ठहराव नहीं है। स्थानीय व यात्री लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सुबह रामबाग से गोरखपुर के लिए एक सीधी ट्रेन चले पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्टेशन पर मात्र 26 ट्रेनों का ही ठहराव है। इससे यहां दिनभर सन्नाटा रहता है।

लिफ्ट बारे में स्टेशन प्रशासन से जानकारी ली जाएगी। प्रयास है कि यात्रियों को यह सुविधा मिले। प्लेटफॉर्म पर शेड को लेकर भी उचित निर्णय लिया जाएगा। – अशोक कुमार, पीआरओ वाराणसी मंडल

गाजियाबाद में बढ़ी प्रॉपर्टी टैक्स की दरों पर हाईकोर्ट की मुहर, कोर्ट ने कहा–कोई वैधानिक खामी नहीं

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स की नई दरों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने 77 पन्नों के विस्तृत निर्णय में कहा कि एक अप्रैल 2025 से लागू की गई बढ़ी दरों में कोई वैधानिक खामी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स की नई दरों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने 77 पन्नों के विस्तृत निर्णय में कहा कि एक अप्रैल 2025 से लागू की गई बढ़ी दरों में कोई वैधानिक खामी नहीं है। इस फैसले के बाद नगर निगम के लिए संशोधित दरों पर टैक्स वसूली का रास्ता साफ हो गया है।

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–174 का हवाला देते हुए कहा कि नगर आयुक्त को संपत्तियों का वार्षिक मूल्य निर्धारण और किराया दरें तय करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार है। शहर को सड़कों की चौड़ाई और विकास के आधार पर ए, बी और सी श्रेणियों में वर्गीकृत करना तर्कसंगत और पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा है।

साथ ही कोर्ट ने कहा कि नई दरें लागू करने से पहले विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाई गई और आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित की गईं। शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि नगर निगम को कुल 318 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं, जिनका परीक्षण और निस्तारण करने के बाद ही अंतिम अधिसूचना जारी की गई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिका जनहित से अधिक राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित प्रतीत होती है।

कोर्ट ने कहा कि प्रशासन ने नगर निगम के राजस्व और नागरिक हितों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है। इसलिए केवल प्रक्रियात्मक आधार पर टैक्स वृद्धि को अवैध नहीं ठहराया जा सकता।

राज्य सरकार का हस्तक्षेप वैध

जब नगर निगम बोर्ड और प्रशासन के बीच गतिरोध की स्थिति बनी, तब राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 116 के तहत हस्तक्षेप किया। कोर्ट ने इस हस्तक्षेप को भी विधिसम्मत ठहराया और कहा कि सार्वजनिक सेवाओं के सुचारु संचालन के लिए राजस्व संग्रह आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि कर में दी गई छूट को समाप्त करना नीतिगत निर्णय है, जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा सीमित होता है।

हाईकोर्ट ने पूछा : राज्य मंत्रिमंडल देवरिया के बस स्टैंड के निर्माण की समयसीमा बताए, छह अप्रैल को होगी अगली सु

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया बस स्टैंड के निर्माण से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से समयसीमा बताने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि निर्माण से संबंधित रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) और ड्रॉफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट का प्रस्ताव अब भी राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए लंबित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया बस स्टैंड के निर्माण से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से समयसीमा बताने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि निर्माण से संबंधित रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) और ड्रॉफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट का प्रस्ताव अब भी राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए लंबित है। मंजूरी की संभावित समयसीमा के संबंध में कोई ठोस जानकारी पेश नहीं की गई। यह यह सवाल मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने अधिवक्ता प्रदीप पांडे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा। याचिका में कहा गया है कि देवरिया में यात्रियों की बढ़ती संख्या के बावजूद अब तक स्थायी और आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो सका। इससे पूर्व कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी थी कि बस स्टैंड का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए लंबित है। कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रस्ताव की स्वीकृति और उसके बाद की कार्ययोजना की समयसीमा स्पष्ट नहीं की जाती, तब तक परियोजना की प्रगति का आकलन संभव नहीं है।

भरण–पोषण वसूली मामले में हाईकोर्ट ने बस्ती के डीएम से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण–पोषण मामले में बस्ती के डीएम से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा कि परिवार न्यायालय की ओर से जारी 13.40 लाख रुपये की वसूली प्रमाणपत्र (रिकवरी सर्टिफिकेट) का पालन अब तक क्यों नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण–पोषण मामले में बस्ती के डीएम से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा कि परिवार न्यायालय की ओर से जारी 13.40 लाख रुपये की वसूली प्रमाणपत्र (रिकवरी सर्टिफिकेट) का पालन अब तक क्यों नहीं हुआ। यह सवाल न्यायमूर्ति प्रवीन कुमार गिरि ने पति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा है।

पति की ओर से गौतमबुद्ध नगर के परिवार न्यायालय के 30 जून 2022 के आदेश को चुनौती दी गई है। आरोप लगाया है कि परिवार न्यायालय ने एकतरफा आदेश देते हुए सीआरपीसी की धारा–125 के तहत पत्नी को भरण–पोषण देने का निर्देश दिया था, जो बकाया राशि बढ़कर 13,40,000 रुपये हो गई है। राशि की वसूली के लिए 26 नवंबर 2025 को परिवार न्यायालय ने बस्ती के डीएम को आदेश भेजा कि रकम भू–राजस्व बकाया की तरह वसूल की जाए। वहीं, बस्ती के हर्रैया तहसीलदार की रिपोर्ट में कहा गया कि पति के नाम कोई चल–अचल संपत्ति नहीं है, जिससे वसूली संभव हो सके।

कोर्ट ने बस्ती के डीएम को निर्देश दिया कि वे मामले की जांच कर व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करें। साथ ही गौतमबुद्ध नगर के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश से भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि भरण–पोषण आदेश लागू कराने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए और आगे क्या कार्यवाही प्रस्तावित है। कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश के अनुपालन में ढिलाई पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़े आदेश पारित किए जाएंगे। अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।

लगान जमा करने से कोई आसामी नहीं बन जाता, 55 साल पुराने भूमि विवाद को लेकर दाखिल अपील खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लगान जमा करने से कोई व्यक्ति संपत्ति का आसामी (स्थायी किरायेदार) नहीं बन जाता। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने देवी दयाल की ओर से कानपुर नगर महापालिका (अब केडीए) के खिलाफ दाखिल 45 साल पुरानी अपील खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लगान जमा करने से कोई व्यक्ति संपत्ति का आसामी (स्थायी किरायेदार) नहीं बन जाता। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने देवी दयाल की ओर से कानपुर नगर महापालिका (अब केडीए) के खिलाफ दाखिल 45 साल पुरानी अपील खारिज कर दी। हालांकि, यह कानूनी लड़ाई साल 1971 में शुरू हुई थी।

याची का दावा था कि वह नगर महापालिका की भूमि पर बतौर किरायेदार खेती करता है। लगान भी जमा करता है। लिहाजा, उसे जमीन से बेदखल न किया जाए। इस पर नगर महापालिका की ओर से दलील दी गई कि याची को केवल एक साल के लिए जमीन लाइसेंस पर दी गई थी। तय अवधि खत्म होने के बाद जमीन पर कब्जा अवैध है। लिहाजा, याची को जमीन छोड़नी होगी। कोर्ट ने पाया कि याची ने खुद को आसामी साबित करने के लिए कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया। याची ने शुरू में खुद को किरायेदार बताया था पर बाद में आसामी अधिकारों की बात करने लगा, जो कानूनन गलत है। कोर्ट ने कहा कि मूलवाद में जिन तथ्यों का हवाला दिया गया है, उसे अपील के स्तर पर बदला नहीं जा सकता।

यदि किसी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए लाइसेंस दिया गया है और वह अवधि समाप्त हो चुकी है तो उसके बाद उसका कब्जा केवल अतिक्रमण कहलाता है। याची कानूनी सुरक्षा का हकदार नहीं रह जाता। –इलाहाबाद हाईकोर्ट

कौन होता है आसामी

आसामी वह व्यक्ति होता है, जो किसी और की जमीन पर खेती करने का अधिकार रखता है पर मालिक नहीं होता।

एक सुपरवाइजर व दो बीएलओ का वेतन रोका, चार को चेतावनी, एसआईआर में लापरवाही पर कार्रवाई

प्रयागराज। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत कार्य में लापरवाही बरते जाने पर फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) ने एक सुपरवाइजर व दो बीएलओ का वेतन रोक दिया है और चार बीएलओ को अंतिम चेतावनी जारी की है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत कार्य में लापरवाही बरते जाने पर फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) ने एक सुपरवाइजर व दो बीएलओ का वेतन रोक दिया है और चार बीएलओ को अंतिम चेतावनी जारी की है। नौ मैपिंग व तार्किक विसंगति में चिह्नित कुल 10,62,435 मतदाताओं में से 10,62,323 वोटरों (99.99 फीसदी) को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 7,56,967 (71.25 फीसदी) मतदाताओं को नोटिस उपलब्ध कराए जा चुके

हैं। वहीं, अब तक कुल 6,54,745 मतदाताओं (61.63 फीसदी) के नोटिसों पर सुनवाई की प्रक्रिया निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पूरी कर चुके हैं।

फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र में इस कार्य में लापरवाही के कुछ मामले सामने आने के बाद निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हीरालाल सैनी ने बीएलओ व सुपरवाइजर के खिलाफ कार्रवाई की है। बूथ नंबर 154 के बीएलओ सौरभ शेखर और बीएलओ अभिताभ मिश्र के वेतन भुगतान पर रोक के आदेश दिए हैं। वहीं, पर्यवेक्षण कार्य में लापरवाही पर बूथ नंबर एक से 10 तक के बीएलओ के सुपरवाइजर रामकुमार का वेतन भी रोकने के आदेश दिए गए हैं। वहीं, असंतोषजनक कार्य पाए जाने पर बूथ नंबर 34, 255, 271 व 341 की बीएलओ क्रमशरू पद्मा शुक्ला, शिवानी पटेल, रेखा सिंह व पूनम लता को अंतिम चेतावनी जारी की गई है। वहीं, नए मतदाता बनने के लिए छह मार्च तक फॉर्म–छह जमा किए जा सकते हैं। ऐसे में लोगों के पास फॉर्म जमा करने के लिए केवल नौ दिन शेष रह गए हैं। इस दौरान फॉर्म जमा करने वालों के नाम एसआईआर के तहत जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिए जाएंगे।

शहर समता विचार मंच द्वारा ऑनलाइन काव्य गोष्ठी होली के उपलक्ष्य में सफलतापूर्वक सम्पन्न

प्रयागराज। शहर समता विचार के तत्वावधान में आयोजित गूगल मीट द्वारा काव्य गोष्ठी रचना सक्सेना की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। इस काव्यगोष्ठी में उमेश श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

काव्यगोष्ठी का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और सरस्वती माँ की प्रतिमा पर माल्यार्पण द्वारा किया गया। सरस्वती वंदना की सुंदर प्रस्तुति सुनीता मिश्रा। काव्य गोष्ठी का संयोजन एवं संचालन उमा मिश्रा प्रीति ने किया।

इस काव्य गोष्ठी में नीता शर्मा, अनीता दुबे, डॉ शशि जायसवाल, शोभा त्रिपाठी,सरिता कपूर, रेणुका पटेल, साधना खरे, संतोष मिश्रा, अनुराधा गर्ग पूनम पांडे सुनीता मिश्रा। रचनाकार बहनों ने सुंदर रचनाओं की प्रस्तुति द्वारा आयोजन में चार चांद लगा दियें। धन्यवाद ज्ञापन उमा मिश्रा प्रीति ने किया।

दारूल इफ़्ता फरंगी महल का ऐलान

लखनऊ, संवाददाता। दारूल इफ्ता वल कज़ा दारूल उलूम फरंगी महल के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली इमाम ईदगाह लखनऊ ने अपने बयान में कहा कि इस्लामी शरीअत के साफ और खुला आदेश है कि वह ईमान वाले जिनको उनके खालिक म मालिक ने माल व दौलत से नवाजा है वह आर्थिक तौर पर कमजोर, जरूरतमन्द और गरीब बन्दों की हर मुमकिन सहायता करें। मालदार मुसलमानों पर हर साल जकात, सद्का फित्र, और कुर्बानी के आदेश इस बात का खुला हुआ सुबूत हैं। उन्होने कहा कि सद्का फित्र अदा करने का हुक्म इस्लामी शरीअत ने इस लिए दिया है कि जिन खुशकिस्मत मुसलमानों ने रमजान माह के रोजों को पूरा कर लिया है वह ईद की नमाज से पहले गरीब मुसलमानों की मदद करें ताकि वह ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि फित्र: एक वाजिब सद्का है। यह उस मुसलमान पर वाजिब होता है जो निसाब का मालिक हो चाहे वह मुसाफिर यो या मुकीम, औरत हो या मर्द, नाबालिग हो या बालिग। मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि हदीस शरीफ में खुजूर, किशमिश, गेहूँ आटा, जौ और दही या पनीर से सद्का फित्र निकालने का हुक्म है। इस लिए जो लोग खुजूर, जौ और किशमिश में से सद्का फित्र अदा करें तो वह इन चीजों में से किसी एक चीज़ से साढ़े तीन किलो या उसकी कीमत दे दें। उन्होने कहा कि जो हजरात गेहूँ से सद्का अदा करें तो वह एक किलो पॉच सौ नव्वे ग्राम या उसकी कीमत कम से कम 70 रूपये प्रति व्यक्ति अदा करें।

रोजेदारों के साथ फूलों की होली खेली चार को

लखनऊ, संवाददाता। चौपटिया से होली पर निकलने वाला परम्परागत जुलूस इस साल अपने 52 साल पूरे कर रहा है। यह जुलूस शुभ संस्कार समिति द्वारा निकाला जाता है। शुभ संस्कार समिति के सचिव ऋद्धि किशोर गौड़ ने बताया कि इस साल भी गंगा जमुना तहजीब के साथ चौपटिया से होली का जुलूस निकलेगा। उन्होंने बताया कि जुलूस में रोजेदारों के साथ फूलों की होली खेली जाएगी। शुभ संस्कार समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया इस बार 4 मार्च को सुबह 9.30 बजे जुलूस कक्कड़ पार्क चौपटिया से शुरू होगा। ऋद्धि किशोर गौड़ ने बताया रमजान का पवित्र माह भी चल रहा है। जुलूस का 70 फीसदी हिस्सा मुस्लिम इलाकों से निकलता है, इसलिए हमेशा की तरह रोजगारों के साथ फूलों की होली खेली जाएगी। उपाध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने बताया कि चौपटिया से जुलूस भोलेनाथ कुआं, अकबरी गेट, विक्टोरिया स्ट्रीट, मेडिकल चौराहा होते हुए चौक पहुंचेगी। हरदोई रोड होते हुए चौपटिया पर जुलूस समाप्त होगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न जगहों पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा स्वागत किया जाएगा। बारात में मुख्य रूप से पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा और विधायक नीरज बोरा मौजूद रहेंगे।

मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड करें जानकारी, संपत्ति विवरण न देने वाले कर्मचारियों पर होगी विभागीय कार्रवाई

लखनऊ, संवाददाता। मानव सम्पदा पोर्टल पर सम्पत्ति का विवरण न देने वाले 47 हजार 816 कर्मचारियों को राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतिम मौका दिया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की तरफ से गुरुवार को सभी एसीएस और प्रमुख सचिवों सहित विभागाध्यक्षों और मण्डलायुक्तों को आदेश जारी कर 10 मार्च तक अपलोड कराने के निर्देश दिया हैं। आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को 31 जनवरी तक सम्पत्ति का विवरण देना था। गोयल द्वारा जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि तक संपत्ति का विवरण दर्ज न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा, उन्हें एसीपी (एसीपी) का लाभ नहीं मिलेगा तथा विदेश यात्रा और प्रतिनियुक्ति के लिए विजिलेंस क्लियरेंस भी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही यदि किसी आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा बिना संपत्ति विवरण अपलोड किए कर्मचारियों का वेतन जारी किया गया है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शासन ने यह भी निर्देश दिया है कि जो कर्मचारी 10 मार्च तक मानव सम्पदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण दर्ज कर देंगे, उन्हें जनवरी और फरवरी 2026 का वेतन भुगतान कर दिया जाएगा।

भाजपा प्रदेश संगठन में बढ़ेगी महिलाओं, दलित और ओबीसी की भागेदारी, होली के बाद होगा ऐलान

लखनऊ, संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान होली के बाद किया जा सकता है। पार्टी संगठन में इस बार नए चेहरों को मौका देने की तैयारी है। खासतौर पर महिलाओं, दलितों और ओबीसी वर्ग की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी मिलने के बाद नई टीम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। लंबी संगठनात्मक प्रक्रिया के बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में नई कार्यकारिणी लगभग तैयार है। बचे हुए कई मंडल अध्यक्षों के नाम मंगलवार और बुधवार को घोषित कर दिए गए हैं। बाकी जिलाध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा भी इसी सप्ताह होने की संभावना है।

सीएमपी डिग्री कॉलेज, प्रयागराज में 'एआई एंड इंडिया: व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन' विषय पर व्याख्यान का आयोजन

प्रयागराज। सीएमपी डिग्री कॉलेज, प्रयागराज में "एआई एंड इंडिया–व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन" विषय पर व्याख्यान का आयोजन 26 फरवरी 2026 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक किया गया। यह कार्यक्रम कॉलेज के न्यू एकेडमिक ऑडिटोरियम तथा ऑनलाइन माध्यम, गूगल मीट के जरिए संपन्न हुआ।

इस व्याख्यान का संयुक्त आयोजन आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (प्फ।ब), इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल (प्ब्) तथा कंप्यूटर एप्लीकेशन विभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में भारत की संभावनाओं, चुनौतियों और अपेक्षाओं पर प्रकाश डालना था।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ. श्याम सुंदरम, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दृ डेटा प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग एवं डेटा साइंस, बजाज फाइनेंस, पुणे महाराष्ट्र रहे।

उन्होंने अपने संबोधन में एआई के बढ़ते प्रभाव, डिजिटल नवाचार और भारतीय उद्योग जगत में इसके उपयोग पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आने वाले समय में शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कार्यक्रम के संरक्षक प्रो. अजय प्रकाश खरे, प्राचार्य, तथा मुख्य संरक्षक के रूप में चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह, अध्यक्ष, केपी ट्रस्ट का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आयोजन में प्रो. अर्चना पांडे ,कन्वीनर, प्प्, प्रो. सरिता श्रीवास्तव ,कोऑर्डिनेटर, प्फ।ब्, डॉ. सुनील कांत मिश्रा ,कन्वीनर, डीसीए सहित विभिन्न विभागों के प्राध्यापक एवं छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

इस अवसर पर सिस्टम एनालिस्ट डॉ. आशुतोष मिश्रा, रत्नेश कुमार दीक्षित, मनीष यादव, गौरव श्रीवास्तव एवं अनुराग सिंह ,कंप्यूटर फैकल्टी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी शिक्षकों ने एआई के शैक्षणिक और व्यावहारिक पहलुओं पर अपने विचार साझा किए।

व्याख्यान के दौरान विद्यार्थियों ने एआई से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञ द्वारा संतोषजनक उत्तर दिया गया। अंत में सुश्री शिवांगी श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए मुख्य वक्ता, प्रबंधन एवं सभी उपस्थित अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम ने छात्रों में तकनीकी नवाचार और डिजिटल भविष्य के प्रति नई सोच एवं उत्साह का संचार किया। आयोजकों ने भविष्य में भी इस प्रकार के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई।

लखनऊ की वरिष्ठ कवियत्री डॉ कुमुद श्रीवास्तव वर्मा कुमुदिनी को अंतरराष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस पर मानद उपाधि से सम्मानित किया गया

लखनऊ। प्रसिद्ध कवियत्री डॉ कुमुद श्रीवास्तव वर्मा कुमुदिनी को विश्व स्तर पर 21फरवरी को मनाये जाने वाले अंतरराष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस के उपलक्ष्य पर मातृभाषा रत्न की मानद उपाधि से नेपाल की प्रसिद्ध संस्था शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में कुमुद श्रीवास्तव को मातृभाषा रत्न की मानद उपाधि सम्मान से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि कुमुद श्रीवास्तव लखनऊ कीएक वरिष्ठ कवियत्री एवं लेखिका हैं,इनकी बहुत सी रचनाएं देश विदेश के विभिन्न समाचार–पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं।इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं,कई साक्षा संकलन एवं एकल काव्य संग्रह छप चुके हैं। कवियत्री को साहित्य संगम संस्थान इंदौर नें विद्या वाचस्पति सम्मान से भी सम्मानित किया है। लेखिका नशा मुक्त समाज अभियान में अहम भूमिका भी निभाती हैं। समाजसेवी के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी कवियत्री अहम भूमिका में रहती हैं। इन्हें हज़ारों ई सर्टिफिकेट एवं दो तीन सौ से ज्यादा प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। कवियत्री का ब्लॉग एवं फेसबुक पेज ष्कुमुद की कलम सेष् नाम से है , जिसके हजारों फालोअर्स हैं।संस्था के अध्यक्ष श्री आनंद गिरि मयालू जी ने यह उपाधि प्रदान करते हुए कहा कि कुमुद श्रीवास्तव वर्मा कुमुदिनी एक बहुआयामी प्रतिभा की धनीं हैं। इन्हें यह सम्मान देते हुए हमें हर्ष हो रहा। कवियत्री को इंदौर की एक साहित्य संस्थान से ष्पद्म गोविन्देष् एवं एक लखनऊ के फाउंडेशन से कुमुदिनी की उपाधि से विभूषित किया गया है।

भूल गए गेस्ट हाउस की वो काली रात, मायावती का सपा पर बड़ा हमला-बहुजन समाज के असली दुश्मन हैं समाजवादी

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड की गूंज सुनाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला बोलते हुए उनके चाल, चरित्र और चेहरे को दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी बताया है। मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि सपा ने हमेशा बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान किया है और दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझा है। मायावती ने 2 जून 1995 की उस खौफनाक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सपा का दलित विरोधी इतिहास पुराना है। मायावती ने कहा कि 1993 में जब सपा–बसपा का गठबंधन हुआ, तब शर्त थी कि दलितों पर अत्याचार रुकेगा, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपना रवैया नहीं बदला। 1 जून 1995 को जब बसपा ने समर्थन वापस लिया, तो अगले ही दिन 2 जून को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में उन पर जानलेवा हमला कराया गया। मायावती ने इसे काली क्रूरता करार दिया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बसपा प्रमुख ने अखिलेश यादव की घेराबंदी करते हुए सवाल पूछा कि सपा आज भले ही दलितों की बात करे, लेकिन उसने हमेशा कांशीराम जी का तिरस्कार किया है। मायावती ने कहा कि सपा सरकार ने कांशीराम जी के नाम पर बने जिलों और संस्थानों के नाम बदल दिए। उन्होंने पूछा कि कांशीराम जी के निधन के बाद सपा सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक तक क्यों नहीं घोषित किया? मायावती ने केवल

दलितों ही नहीं, बल्कि मुस्लिमों को भी सपा से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह सपा के शासनकाल में भी बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें लाखों मुस्लिम परिवार बर्बाद हो गए। मायावती ने गंभीर आरोप लगाया कि सपा अपने भड़काऊ आचरण से भाजपा को राजनीतिक जमीन तैयार करके देती है। उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा एक–दूसरे की जरूरत बनकर राजनीति करते हैं, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। मायावती ने अंत में कहा कि आज उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा का राज है, तो उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी ही है। सपा की जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति के कारण ही आज बहुजन समाज और मुस्लिम वर्ग त्रस्त है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सपा के इस बहुरूपिया चेहरे को पहचानें और सावधान रहें।

वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं देना चाहती केन्द्र सरकार

उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरेगी पार्टी : चेतन शर्मा

लखनऊ, संवाददाता। क्रान्तिकारी स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर आज यहां इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुये अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा करते हुये कहा है कि केन्द्र सरकार वीर सावरकर को भारत–रत्न देने के लिये गंभीर नहीं है। अधिवेशन में पार्टी के सर्वसम्मति से नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि वीर सावरकर ने अपने युवावस्था में ही अभिनव भारत संगठन की स्थापना कर पराधीन भारत में क्रान्ति की ज्वाला प्रज्जवलित की थी, उन्होंने केवल स्वतंत्रता का स्वप्न नहीं देखा बल्कि उसके लिये कालकोठरी में अमानवीय यातनायें सही। अंडमान की सेल्युलर जेल की दीवारें आज भी उस तप, त्याग और तेज की साक्षी है, ऐसे व्यक्तित्व को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी वीर सावरकर को भारत रत्न दिये जाने को लेकर कह चुके है कि सावरकर के योगदान को देखते हुये यदि उन्हें भारत–रत्न मिलता है तो इससे भारत–रत्न का सम्मान होगा।

लखनऊ सिविल कोर्ट में पिस्टल-कारतूस समेत 2 युवक गिरफ्तार

लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ सिविल कोर्ट परिसर से 2 युवकों को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक आरोपी का केस एनआईए कोर्ट में चल रहा है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर रही है। कोर्ट परिसर में हथियार ले जाने की मंशा अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार भानु प्रताप यादव राजाजीपुरम इलाके का रहने वाला है।

उसी को गुझिया कहते

(छप्पय)

मंदिर राधा रमन सुहाना है वृंदावन।
गुझिया का मधु स्वाद जहाँ भाता कान्हा–मन।
तेरह सौ के मध्य सभी जाने हैं जिसको।
भारत का मिष्ठान्न सभी कहते हैं उसको।
कठनाई में जो नहीं तजता प्रेम मिठास को।
सदा जीतता है वही,अपनों के विश्वास को।।

दिल्ली,राजस्थान जिसे गुजिया हैं कहते।
यूपी और बिहार उसी को गुझिया कहते।
हैं हल्का सा है फ़र्क स्वाद में इन दोनों के।
लेकिन बनकर एक सदा रहते लोगों के।
रंगों का त्यौहार है खुशियों की भरमार है।
प्रेम और सौहार्द की अनुपम मधुर बयार है।।

डॉ. प्रदीप चित्रांशी
लूकरगंज, प्रयागराज

भारतीय मजदूर संघ द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान पर उमरे कर्मचारी संघ ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया

प्रयागराज। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, प्रयागराज पर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय अधिवेशन ख्पुरी, उड़ीसा, में लिए गए निर्णय के तहत कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली, बोनस की सीमित सीमा बढ़ाकर 18000 रुपये करने

और नए श्रम कानूनों को लागू करने जैसे प्रमुख मजदूरों को लेकर हुंकार भरी। संघ के उद्देश्यों श्री रूपम पाण्डेय जी के निर्देश पर मंडल मंत्री श्री आशीष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, प्रयागराज को प्रधानमंत्री एवं श्रम मंत्री के नाम निर्देशन ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संयुक्त मंडल मंत्री श्री सत्यम गुप्ता जी, श्री श्याम जी शुक्ला जी, डीआरएम ऑफिस शाखा के शाखा मंत्री श्री सनत कुमार तिवारी, श्री संतोष शर्मा जी, आरके सिंह जी, सुरेश शर्मा, ज्ञानेंद्र यादव, ललित कुमार इत्यादि मौजूद रहे।

लखनऊ के प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. पी. सी. गुप्ता को भारतीय डिजाइन पेटेंट प्राप्त

लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ स्थित प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश डॉ. पी. सी. गुप्ता को "।प्–ठेंमक क्मअपबम वित ठनेपदमैं जतंजमहल च्संददपदह दक त्पो थ्वतमबेंजपदह" शीर्षक से विकसित नवाचार हेतु भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा डिजाइन पंजीकरण प्रमाणपत्र (प्दकपंद क्मेपहद च्ंजमदज) प्रदान किया गया है। यह पंजीकरण डिजाइन अधिनियम, 2000 एवं डिजाइन नियम, 2001 के अंतर्गत प्रदान किया गया है द्य यह अभिनव डिजाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (।ए) आधारित उपकरण से संबंधित है, जो व्यवसायिक रणनीति निर्माण (ठनेपदमें जतंज. महल च्संददपदह) एवं जोखिम पूर्वानुमान (त्पो थ्वतमबेंजपदह) में सहायक है। यह उपकरण आधुनिक आर्थिक विश्लेषण, डेटा आधारित निर्णय–निर्माण तथा संस्थागत प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस उपलब्धि में डॉ. पी. सी. गुप्ता के साथ अन्य सह–आविष्कारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें डॉ. महेन्द्र कुमार नामदेव, डॉ. मुस्ताक आलम, पूजा उपाध्याय, डॉ. किरण सचदेवा, डॉ. श्वेता सिंह, सुमोना घोष, विशाल मिश्रा, अवधेश यादव एवं अपराजिता श्रीवास्तव शामिल हैं। डॉ. पी. सी. गुप्ता, जो कि लखनऊ के एक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् एवं अर्थशास्त्री हैं, एवं डॉ. मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ अर्थशात्री द्वारा भी अपनी अर्थशास्त्र पर पुस्तकों हेतु सराहना पत्र एवं मार्गदर्शन पा चुके है ने इस उपलब्धि को शिक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार के समन्वय का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह डिजाइन भविष्य में उद्योग, शिक्षा एवं नीति–निर्माण के क्षेत्र में रणनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावी बनाएगा। शैक्षणिक एवं बौद्धिक जगत में इस उपलब्धि को अत्यंत गौरवपूर्ण माना जा रहा है। यह न केवल संस्थान बल्कि लखनऊ शहर एवं प्रदेश के लिए भी गर्व का विषय है।

नगर निगम में बड़ा खुलासा, 23 अफसरों पर गिरी गाज, फर्जी निस्तारण का घोटाला उजागर

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम से जुड़ा एक बड़ा प्रशासनिक खुलासा सामने आया है। लखनऊ नगर निगम के 23 अधिकारियों पर 300 से अधिक शिकायतों के फर्जी निस्तारण का आरोप लगा है। मामले के सामने आने के बाद निगम में हड़कंप मच गया है। जांच में पता चला है कि कई मामलों में बिना काम किए ही सड़क मरम्मत पूरी दिखा दी गई। सीवर लीकेज की शिकायतें भी कागजों में निपटा दी गईं, जबकि जमीनी स्तर पर समस्याएं जस की तस बनी रहीं। हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी म्यूटेशन से जुड़े मामलों में भी भारी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। शिकायतों का समाधान दिखाकर फाइलें बंद कर दी गईं, जबकि संबंधित नागरिकों को राहत नहीं मिली। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद जांच में तेजी आई। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने सभी 23 अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। जोनल अधिकारियों से लेकर चीफ इंजीनियर और एक्सईएन स्तर के अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं। विशाख जी के पत्र के बाद मामले में कार्रवाई की रफ्तार और तेज हो गई। फर्जी निस्तारण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है और दोषी अधिकारियों की सूची अंतिम चरण में बताई जा रही है। नगर निगम शासन को विस्तृत रिपोर्ट भेजने की तैयारी में है। शहर में प्रशासनिक सख्ती के बीच बड़े फेरबदल के संकेत भी मिल रहे हैं।

सम्पादकीय.....

मोदी की इजरायल यात्रा पर सवाल

पूरी दुनिया की निगाहें इस समय ईरान के हालात पर टिकी हैं, जहां अमेरिका ने अपने युद्धपोत तैनात किए हुए हैं और कई दिनों से लगातार धमकियां दे रहा है कि वो जंग की शुरुआत कर देगा। खुद भारत ने सोमवार 23 फरवरी को ईरान में अपने नागरिकों से कहा है कि वे फौरन ईरान छोड़ दें। यानी ईरान पर किसी भी समय अमेरिकी हमला हो सकता है। लेकिन 23 फरवरी को ही इजरायली कैबिनेट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की कि भारत क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग के लिए एक हेक्सागोनल गठबंधन में शामिल होगा। इसके बाद तय हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी 25 फरवरी को दो दिन के इजरायल दौरे पर जा रहे हैं यानी जब पूरा मध्यपूर्व बड़े संकट से गुजर रहा है, उस समय इजरायल एक अलग वैश्विक गठजोड़ तैयार कर रहा है और भारत उसका हिस्सा बनने जा रहा है। इजरायल के राजदूत रेयुवेन अजार ने एक वीडियो पोस्ट में कहा कि दोनों देश रक्षा और सुरक्षा समझौतों को श्अपडेटश करेंगे। गौरतलब है कि हेक्सागोनल एलायंस (हेक्सागोन ऑफ एलायंसेज) इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा 22 फरवरी को कैबिनेट बैठक में घोषित एक प्रस्तावित रणनीतिक भू–राजनीतिक ढांचा है। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व और उसके आसपास के क्षेत्र में आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है, खासकर श्रेडिकल शिया एक्सिसश (ईरान और उसके सहयोगी) और उभरते रेडिकल सुन्नी एक्सिस के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना। नेतन्याहू ने इसे श्हेक्सागोनश (छह भुजाओं वाला) कहा, जो एक नेटवर्क्ड गठबंधन का प्रतीक है। इस नेटवर्क को खड़ा करने में बड़ी चालाकी से शब्दों का खिलवाड़ किया गया है वर्ना रेडिकल यानी कट्टरपंथी शिया और सुन्नियों के खिलाफ छह भुजाओं वाला गठबंधन खड़ा करना, धर्म के आधार पर विरोध को बढ़ावा देना ही है। इजरायल संप्रभु देश है और उसकी जो मर्जी वह करे। लेकिन इस हेक्सागोन नेटवर्क में इजरायल केंद्रीय भूमिका निभाएगा, जबकि भारत को प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में विशेष महत्व दिया गया है। अन्य सदस्यों में ग्रीस और साइप्रस (भूमध्यसागरीय भागीदार) शामिल हैं साथ ही कई और अरब, अफ्रीकी और एशियाई देशों को शामिल करने की भी योजना है, हालांकि उनके नाम अभी साफ नहीं किए गए हैं। यह अब्राहम समझौते पर आधारित है लेकिन गैर–अरब शक्तियों जैसे भारत को शामिल करके विस्तारित किया जा रहा है। बता दें कि 2020 में इजरायल ने अमेरिका की मध्यस्थता में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को जैसे अरब देशों के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए अब्राहम समझौता नाम से राजनयिक समझौता किया था। जिसके तहत इस समझौते का उद्देश्य मध्यपूर्व में शांति, स्थिरता और व्यापार को बढ़ावा देना है। अब इसी का विस्तार करते हुए इसमें भारत को भी शामिल किया जा रहा है। यानी अमेरिका के बाद अब इजरायल भी तय करने लगा है और बताने लगा है कि भारत क्या करने जा रहा है। इजरायल और अमेरिका पूरी दुनिया में किस तरह अपनी खुफिया एजेंसियों और हथियारों के बल पर कमजोर देशों की आंतरिक और बाहरी नीतियों को निर्धारित करते हैं, यह तो विश्व राजनीति की खुली किताब में दर्ज है। लेकिन भारत किस तरह अपने आप को इतना कमजोर कर रहा है, यह चिंता की बात है। प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा का मकसद और वक्त दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। जिस इजरायल ने गजा में आम लोगों का कत्लेआम किया और उसके बाद ईरान के साथ जंग पर उतर आया, अभी अमेरिका भी ईरान पर हमले के लिए तैयार बैठा है, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री मोदी इजरायल जा रहे हैं। कई मुस्लिम देशों ने क्षेत्र में सैन्य तनाव से बचने की अपील की है। ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री का तेल अवीव जाना स्वाभाविक रूप से प्रतीकात्मक अर्थ पैदा करता है–चाहे नई दिल्ली की आधिकारिक मंशा कुछ भी क्यों न हो। गौरतलब है कि भारत लंबे समय से श्रणनीतिक संतुलनश की नीति पर चलता रहा है– उसने इजरायल के साथ मजबूत रक्षा सहयोग के संबंध बनाए, तो दूसरी ओर खाड़ी देशों और ईरान के साथ गहरे आर्थिक और ऊर्जा संबंध भी बनाए रखे। लेकिन मोदी सरकार ने इस संतुलन को बिगाड़ दिया है। यदि भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत उसकी कूटनीति रही है, तो उसे प्रतीकों की राजनीति से भी उतनी ही सावधानी बरतनी चाहिए। नरेन्द्र मोदी की इजरायल यात्रा प्रतीकों की राजनीति का ही हिस्सा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिकी सैन्य जमावड़े के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के समय पर संसद विदेश मामले की स्थायी समिति ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। समिति की बैठक सोमवार 23 फरवरी को हुई, जिसमें विदेश मंत्रालय के बजटीय आवंटन पर चर्चा के दौरान शशि थरूर ने इस यात्रा की औचित्य पर सवाल किया, खासकर जब भारत ने ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों को वहां से निकलने की सलाह जारी की है और अमेरिकी हमले की आशंका जताई गई है। गौरतलब है कि नरेन्द्र मोदी नौ साल बाद फिर से इजरायल जा रहे हैं।

वर्चस्व को नकारना भारतीय संघ का स्वधर्म है

योगेन्द्र यादव

अब तक हम भारत गणराज्य के स्वधर्म के 3 सूत्रों की व्याख्या कर चुके हैं। अंतिम कड़ी में यहां हम चौथे सूत्र यानी संघवाद की चर्चा करेंगे, जिसे फैडरलिज्म कहा जाता है। संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत 'राज्यों का संघ होगा'। लेकिन अंग्रेजी में इसे 'फैडरेशन' नहीं 'यूनियन ऑफ स्टेट्स' कहा गया। जाहिर है इस असहजता की पृष्ठभूमि थी देश का बंटवारा, जिसकी परछाई संविधान निर्माण पर देखी जा सकती है। संविधान निर्माता अब किसी और बंटवारे से बचने के लिए केंद्र को खुला हाथ देना चाहते थे। लेकिन 'फैडरेशन' का इस्तेमाल न करने के पीछे यह आग्रह भी रहा होगा कि राष्ट्रीयता और क्षेत्रीयता को बने–बनाए यूरोपीय सांचे में न ढाला जाए। संविधान निर्माता समझ रहे थे कि भारत न तो यूरोपीय अर्थ में एकात्मक या केंद्रीकृत है और न ही अमरीकी अर्थ में संघात्मक। भारत की एकता न तो समरूपता की चाह रखती है, न ही बहुलता का महिमामंडन करती है। 'यूनियन' जैसा ढीला शब्द भारत की इस अनूठी बुनावट को बनाए रखने और हमें अपने रिश्तों को अपने तरीके से परिभाषित करने की आजादी देता है। इस अनूठेपन में भारत गणराज्य के स्वधर्म का चौथा सूत्र छुपा है। यह एक मूल्य नहीं, बस एक एहसास है, भारत की बुनावट की सहज स्वीकारोक्ति है। यह भाव भारतीय दर्शन में है, इतिहास में है, संस्कृति में है और जनमानस में है। भारतीय दर्शन की विशेषता यही है कि इसका नैतिक बोध किसी शाश्वत नियमों से यांत्रिक रूप से बंधा नहीं है। नैतिकता देश, काल और पात्र सापेक्ष है। यह समझ किसी एक दार्शनिक या धार्मिक परंपरा से नहीं जुड़ी। वैदिक काल से लेकर धर्मशास्त्र तक, बौद्ध और जैन दर्शन में, सूफी संतों से दारा शिकोह तक सभी में यह भाव मौजूद है। भाषा चाहे धर्म और विवेक की हो या अनेकान्तवाद और प्रतीत्यसमुत्पाद अथवा अहवाल, इज्तेहाद, तमीज और मुनासबत की, इन सबने परिस्थिति सापेक्ष नैतिकता की व्याख्या की। इनके लिए विविधता एक मूल्य या आदर्श नहीं था, बल्कि सामाजिक हकीकत थी, जिसे इन्होंने सहज रूप से ग्रहण किया। यही भाव सामाजिक और राजकीय नियम–कानून को एकांगी होने से रोकता है। देशाचार या देश धर्म की अवधारणा इसी भाव की अभिव्यक्ति है। हर इलाके और समुदाय के अपने अलग आचार–व्यवहार, रीति–रिवाज हैं। सबको एक ही चाल में ढालने की बजाय इस विविधता का सम्मान करना चाहिए। जहां शास्त्र चुप हैं, वहां सामाजिक मान्यता मर्यादा का स्रोत है। धर्म हमेशा संस्कार का स्रोत नहीं होता। संस्कार भी धर्म का स्रोत हो सकता है। यही विचार सल्तनत और मुगल काल में भी विकसित हुआ। इसके चलते समस्त प्रजा पर शरिया और शाही कानून थोपने की बजाय राज्य के बड़े इलाके और समुदाय के लिए 'उर्फ' यानी स्थानीय तौर–तरीके और सामाजिक मान्यता को स्वीकार किया गया। यह न सिर्फ रणनीति थी, न सिर्फ राजनीतिक दर्शन। यह एक गहरी राजनीतिक समझ थी। यह भाव और समझ भारत गणराज्य की बुनियाद में है। भारतीय राज्य केवल एक आधुनिक 'सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न' राज्य नहीं है। वह तो भारतीय राज्य की ऊपरी परत है। उसके नीचे इतिहास की कई और परतें हैं। भारत में राजसत्ता कभी भी सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं रही। प्राचीन काल में सम्राट चाहे जितना बड़ा हो, उसकी सत्ता सीमित थी। न तो वह कानून का एकमात्र निर्धारक था, न धार्मिक और सामाजिक तौर तरीकों में दखल दे सकता था तथा न ही अविभाजित वफादारी मांग सकता था। राजा की सत्ता समाज की सत्ता के साथ थी, उसके ऊपर नहीं। मुगल राज आने के बाद राज्य की वित्तीय, सैन्य और संस्थागत क्षमता बहुत बढ़ी। लेकिन मुगल बादशाह को भी अपनी संप्रभुता में सांझेदारी करनी पड़ती थी–जमींदारों, स्थानीय राजाओं, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के साथ। मुगल साम्राज्य में न तो एक जैसा कानून था, न एक नागरिकता और न ही धार्मिक और सामाजिक मामलों का एकाधिकार। राज्य सत्ता की इस बुनावट पर औपनिवेशिक राज ने आधुनिक राष्ट्र और राज्य की परत बिछाई। इसने हमारे समाज और राजनीतिक सत्ता के स्वरूप में बुनियादी बदलाव किए। बेशक भारत गणराज्य का औपचारिक स्वरूप एक राष्ट्र–राज्य की आधुनिक परिपाटी के मुताबिक चलता है लेकिन व्यवहार में भारतीय सभ्यता की गहरी बुनावट ने आधुनिक राष्ट्र, प्रभुत्व संपन्न राज्य और लोकतांत्रिक राजनीति का रूप रंग बदल दिया है। एकछत्र केंद्रीयकृत प्रभुत्वशाली सत्ता हमारी सभ्यता का मिजाज नहीं है। इसलिए व्यवहार में आधुनिक राज्य की शक्ति हमेशा मर्यादित रही है। अकेंद्रित सत्ता, सांझा प्रभुत्व और गठबंधन आधारित शक्ति ही हमारे समाज का स्वधर्म रहा है। भारतीय संविधान में संघ या यूनियन की अवधारणा को इस रौशनी में देखना उचित होगा। यह यूरोप–अमरीका की काट का फैडरेशन नहीं है। भारतीय संघ में सत्ता का बंटवारा पश्चिमी फैडरेशन से अलग किस्म का है। भारतीय संघ अमरीका की तर्ज पर अनेक प्रभुत्व संपन्न राज्यों के स्वैच्छिक समझौते से बना एक राज्य नहीं है। न ही यह सोवियत संघ वाले अंदाज में अनेक राष्ट्रों के मिलन से बना एक बहुराष्ट्रीय राज्य है। भारत गणराज्य की बुनियाद औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ संघर्ष से पैदा हुई एकजुटता में है। इस गणराज्य की क्षेत्रीय इकाइयों ने वयस्क होने के बाद एक दूसरे से संबंध बनाने का फैसला नहीं लिया। इनकी पैदाइश ही एक साथ हुई। यहां शक्ति के बंटवारे का मतलब केवल कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बंटवारा नहीं है। सरकार और समाज में सत्ता का बंटवारा हमारा स्वधर्म है। यहां सत्ता के स्वायत्त दायरे की जरूरत सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार के बीच नहीं, बल्कि उसके बहुत नीचे पंचायत और मुहल्ला सरकार तक है। यहां राष्ट्रीय एकता बाकी सब भाषाई और क्षेत्रीय पहचान को खत्म करके नहीं बनती। यहां की तमाम भाषाई संस्कृतियों की पहचान भारत से अलग नहीं है, भारत पर निर्भर भी नहीं है। दरअसल भारत की पहचान इन सब पहचानों को जोड़ कर बनती है।

भारतीय संघ की बुनियाद में वर्चस्व को नकारने वाला एक अलिखित समझौता है। केंद्र सरकार, भाषा या सांप्रदायिक लिहाज से बहुसंख्यक समाज या कोई भी सांस्कृतिक समुदाय अपना वर्चस्व स्थापित नहीं करेगा। इसलिए हमारी सभ्यता के मिजाज के खिलाफ जाकर एक देश, एक भाषा, एक धर्म, एक जाति की तर्ज पर राष्ट्रीय एकता को एकरूपता की तरह परिभाषित करना हमारे स्वधर्म का विलोम है।

यह प्रधानमंत्री की शर्मिंदगी नहीं, बौखलाहट है

अनिल जैन

देश की राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों भारी अफरातफरी के माहौल में संपन्न हुए अंतरराष्ट्रीय आर्टिफिशल इंटेलिजंस यानी एआई समिट के दौरान कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित उनकी पूरी सरकार, उनकी पार्टी और उसका इको सिस्टम बेहद खफा और परेशान हैं। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में अपने गुस्से का इजहार करते हुए आहत स्वर में कांग्रेस के नेताओं को श्नंगाश कहते हुए उन पर विदेशी मेहमानों के सामने देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। तमाम मंत्री और भाजपा के नेता मोदी से भी एक कदम आगे बढ़कर राहुल गांधी को श्देशद्रोहीश और श्लफंगाश करार दे रहे हैं। चूंकि सरकार और भाजपा परेशान है, लिहाजा उसके प्रचार तंत्र की भूमिका निभाने वाले मीडिया का परेशान होना भी लाजिमी है, सो वह भी कुछ इसी तरह के लहजे में राहुल गांधी और कांग्रेस को कोस रहा है। दरअसल मोदी के लिए लोकतंत्र का मतलब महज किसी भी तरह से चुनाव जीतना है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्ता, विपक्ष से संवाद और सरकार से असहमति आदि के लिए उनके लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। इसलिए वे अपनी सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को देशविरोधी करार देने में कोई देरी या संकोच नहीं करते। इसकी वजह यह भी है कि उनकी राजनीतिक परवरिश लोकतांत्रिक माहौल में नहीं बल्कि एकचालकानुवर्तित्व के माहौल में हुई है। उन्होंने सत्ता में आने से पहले के अपने राजनीतिक जीवन में सरकारविरोधी किसी आंदोलन में शिरकत नहीं की और जेल जाना तो दूर, किसी पुलिस थाने का मुंह तक नहीं देखा। इसलिए उन्हें किसी भी मुद्दे पर अपनी सरकार का विरोध बेहद अटपटा लगता है और वे बौखला जाते हैं। मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया के अधिकांश देशों की यात्राएं कर चुके हैं। प्रधानमंत्री और गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले भी आधुनिक विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र कहे जाने वाले अमेरिका की यात्रा तो उन्होंने कई बार की है, जैसा कि वे खुद कई मर्तबा बतला चुके हैं। इसके बावजूद वे इस तथ्य से अनजान हैं कि लोकतांत्रिक देशों में अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के दौरान किसी मुद्दे को लेकर विरोध–प्रदर्शन होना कोई नई बात नहीं है। अमेरिका सहित यूरोप के तमाम देशों में अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के मौके पर वहां के राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, छात्र या मानवाधिकार संस्थाएं किसी मुद्दे को लेकर विरोध और प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन वहां विरोध करने वालों को देशद्रोही कहना तो दूर गिरफ्तार भी नहीं किया जाता है। मोदी ने खुद भी प्रधानमंत्री के नाते ऐसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में शिरकत की है और कुछ आयोजनों के दौरान तो वहां मोदी के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए हैं। हमारे ही देश में पहले कई अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के मौके पर ऐसे विरोध–प्रदर्शन हुए हैं। 1982 में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों के आयोजन के खिलाफ लोकदल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कुछ घंटों के लिए हिरासत में लिया था और फिर छोड़ दिया था। किसी ने उन्हें श्देशद्रोहीश या लोकदल के नेता चौधरी चरणसिंह को नंगा नहीं कहा था। उसके बाद दिल्ली में ही 1983 में गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। उस आयोजन के मौके पर लोकदल और वामपंथी दलों ने कुछ ही समय पहले असम में हुए शर्मनाक नेल्ली नरसंहार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन किया था, लेकिन किसी ने प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही नहीं कहा था और न ही देश की छवि खराब होने का राग अलापा था। दिल्ली में ही 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के मौके पर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया था। तब भी किसी ने प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही नहीं कहा और न ही किसी को गिरफ्तार किया। बहरहाल एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध–प्रदर्शन रणनीतिक रूप से सही था या गलत, इस पर तो बहस हो सकती है मगर इसमें शर्मसार होने जैसी कोई बात नहीं है। फिर भी प्रधानमंत्री और उनके तमाम सहयोगी नाराज हुए जा रहे हैं। जबकि एआई समिट के दौरान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के अलावा ऐसी कई बातें हुई हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को शर्मसार होना चाहिए था, लेकिन वे नहीं हो रहे हैं। आयोजन के पहले दिन प्रधानमंत्री के फोटो सेशन के लिए आयोजन स्थल को पांच घंटे के लिए पूरी तरह खाली करा लिया गया था, जिससे विदेशी मेहमानों को काफी परेशानी हुई और उस दौरान कई विदेशी मेहमानों के कीमती सामान चोरी हो गये परन्तु इस पर किसी को शर्म नहीं आ रही है। एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन में बने रोबोटिक डॉग को अपने यहां निर्मित हुआ बताते हुए उसका प्रदर्शन किया। यही नहीं, उस चीनी रोबोटिक डॉग को भारत सरकार के सूचना तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी भारतीय आविष्कार और प्रधानमंत्री मोदी के विजन का परिणाम बताया, जिससे दुनिया भर में भारत की किरकिरी हुई, लेकिन मोदी सहित किसी को भी शर्म ने छुआ तक नहीं। गौरतलब है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी ने इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी को टॉप यूनिवर्सिटी के अवार्ड से नवाजा था। वैसे एआई समिट के अलावा भी पिछले 12 वर्षों के दौरान देश में ऐसे कई वाकये हुए हैं जिनसे दुनिया में भारत की छवि खराब हुई है लेकिन किसी को शर्म नहीं आई– न प्रधानमंत्री को, न उनकी सरकार व पार्टी को और न ही मुख्यधारा के मीडिया को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने देश के मीडिया के समक्ष कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री मोदी का कैरियर बर्बाद कर सकता हूं, इसलिए मुझे खुश करना मोदी की मजबूरी है। संप्रभुता संपन्नता भारत को अपमानित करने वाले इस बयान पर किसी को शर्म नहीं आती। यही नहीं, ट्रंप ने 50 से अधिक बार कहा है कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान को धमका कर उनके बीच सीजफायर करवाया। ट्रम्प के इस दावे पर किसी का जमीर नहीं जागता। सुदूर पूर्वोत्तर के मणिपुर में जब एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय की महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर घुमाते हैं, जिसकी खबरें दुनिया भर के मीडिया में प्रमुखता से जगह पाती हैं, तब भी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी को शर्म नहीं आती है। देश में हिंदू राष्ट्र और सनातन का राग अलापने वाले महंत और महामंडलेश्वर जब यौन दुराचार के मामलों में रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तब भी किसी को शर्म नहीं आती। उस समय भी किसी को शर्म नहीं आती जब बलात्कार के सजायाफ्ता लोगों की सजा माफ कर दी जाती है और उनके जेल से रिहा होने पर हार–फूलों से उनका स्वागत किया किया जाता है। भारत की छवि तब भी खराब नहीं होती है जब देश की उच्च अदालतें बलात्कार जैसे वीभत्सतम अपराध की उलजुलूल व्याख्या करते हुए बलात्कारियों की हौसला अफजाई करती हैं, लेकिन किसी को शर्म नहीं आती। जब भाजपा शासित उत्तराखंड में 20 साल की एक युवती को सत्तारूढ़ दल के प्रभावशाली नेता अपनी हवस का शिकार बनाकर उसकी हत्या कर देते हैं, तब भी किसी को शर्म नहीं आती है।

रचना सक्सेना की कुण्डलियाँ

कल का किसको है पता, कौन यहाँ दे घात।
वर्तमान ही बस यहाँ, यही सदा प्रज्ञात।।
यही सदा प्रज्ञात, आज फिर जी लो खुलकर।
काम करो कुछ नेक, रहो सबसे मिलजुल कर।।
कहती रचना आज, मिलेगा अच्छा ही फल।
पावन रखें विचार, बनेगा अच्छा फिर कल।।

कल का किसको है पता, मन की आँखें खोल।
भाषा कलुषित मत करो, मीठे बोलो बोल।।
मीठे बोलो बोल, उसे सब याद करेंगे।
नश्वर यह संसार, एक दिन सभी मरेंगे।।
कहती रचना आज, बनो तुम शीतल सा जल।
मीठे हो जब बोल, तभी सब याद करें कल।।

रचना सक्सेना
अलोपीबाग
प्रयागराज

भागवत जी के भाषण को सही नजरिए से देखा जाना चाहिए

विश्वास डावर

सरसंघचालक (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख) श्री मोहन भागवत जी के भाषण को सही नजरिए से देखा जाना चाहिए–जिसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अपना असली धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया था, उनका वापस

स्वागत है–इस बात में कोई सांप्रदायिक भावना नहीं दिखनी चाहिए। जैसा कि इतिहास बहुत साफ है, भारत में सैंकड़ों सालों तक, मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं को अपना धर्म छोडने के लिए मजबूर किया। इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने के लिए, यूरोपीय शासकों ने उन पर मुकद्दमा चलाया और कई मामलों में, धर्म के आधार पर अमानवीय अत्याचार और बेरहमी से हत्याएं हुईं। भारत में इस्लाम और ईसाई धर्म को जबरदस्ती और कई दूसरी चीजों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद और सेवा की आड़ में फैलाया गया। भागवत जी की बात बहुत सीधी और सरल है–अगर कोई अपनी मर्जी से अपने असली धर्म में वापस आना चाहता है, तो हमें हिंदू समाज के तौर पर उनका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने बहुत ज्यादा दबाव और ऐसी शर्तों के तहत अपना असली धर्म छोड़ा जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं। मुझे इसमें कोई गैर–धर्मनिरपेक्ष काम नहीं दिखता, क्योंकि इसमें दबाव, लालच या किसी भी गलत तरीके का कोई तत्व नहीं है। भारत जैसे आजाद और स्वतंत्र देश में, अपनी पसंद से धर्म बदलना गैर–कानूनी नहीं है। हिंदू धर्म (सनातन) सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं था, बल्कि इंडो–चाइना, इंडोनेशिया और दूसरे दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों तक फैला हुआ था। इंडोनेशिया में ड्क्षहदू धर्म का काफी ज्यादा उभार हो रहा है, जहां मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी है। हिंदू–बहुल द्वीप बाली के अलावा, जावा और सुमात्रा जैसे द्वीपों पर हिंदू आबादी बढ़ रही है और नए हिंदू मंदिर बन रहे हैं। कुछ भी जबरदस्ती या किसी और गलत तरीके से नहीं हो रहा, यह सनातन धर्म की आध्यात्मिक आवाज है। इंसान की जिंदगी में शांति, खुशहाली और सुकून लाना ही सनातन धर्म कई यूरोपियन देशों जैसे पोलैंड, एस्टोनिया वगैरह में कर रहा है। हिंदू (सनातन धर्म) ने कभी किसी को धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। यह महान आध्यात्मिकता और फिलॉसफी की भावना है–सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सबके लिए अच्छा सोचना और अपने आस–पास के सभी लोगों के साथ शांति से रहना। सनातन के इन बुनियादी सिद्धांतों ने इसे हजारों सालों तक सभी मुश्किलों और हमलों के बावजूद जिंदा रहने में मदद की है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो धर्म के हिसाब से पूरी तरह बदल गए हैं और स्पेन इसका एक उदाहरण है। स्पेन 700 सालों तक मुस्लिम शासन के अधीन था और 8वीं सदी की शुरुआत (711 ए.डी.) से 15वीं सदी के आखिर (1478 ए.डी.) तक वहां मुस्लिम आबादी थी। इस दौरान, लगभग 800 सालों तक, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच लड़ाइयां लड़ी गईं, जिन्हें रिकोनक्विस्टा के नाम से जाना जाता है, जिसके नतीजे में स्पेन फिर से एक ईसाई देश बन गया। इतिहास साफ दिखाता है कि जहां भी इस्लामी राज कायम हुआ, पूरे देश मुस्लिम बन गए। इसी तरह, जहां यूरोपियन राज करते थे, वे ईसाई बन गए। हालांकि, भारत और सनातन धर्म अपनी पहचान बनाए रखने में कामयाब रहे, भले ही दबाव में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुए, जिनको बदला जा सकता है और लोगों को घर वापसी करनी चाहिए। यह बात कि सनातन हजार सालों तक उन सभी हमलों से बचा रहा, सनातन की सबसे बड़ी ताकत है। इसके उलट, भारत का सनातन धर्म बिना किसी हिंसा के बचा रहा और फला–फूला। यह जीने का एकमात्र तरीका है, जो हमारे देश को बिना किसी डर, गोलियों, गोले या अमानवीय कामों के आगे बढने और फलने–फूलने में मदद कर सकता है, जिससे आम लोगों को इंसानी दुख और तकलीफ होती है। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने भागवत जी के इस सुझाव की आलोचना की है कि ड्क्षहदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिएं, जिन्हें अच्छी परवरिश दी जा सके। इसे भी सही नजरिए से देखना चाहिए। कम बर्थ रेट की वजह से, देखिए कि जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और बैल्जियम जैसे यूरोपियन देशों में क्या हो रहा है, जहां की आबादी में युवाओं का प्रतिशत बहुत कम है। उन्हें दिक्कतें आने लगी हैं, कम युवा आबादी की वजह से आप्रवासियों से इन देशों में कानून–व्यवस्था की बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जापान जैसे देशों में भी कम जन्म दर की वजह से बूढ़ी होती आबादी की दिक्कतें देखी गई हैं। भारत में, ज्यादातर ड्क्षहदुओं की आबादी में कम जन्म दर डेमोग्राफिक इम्बैलेंस पैदा कर सकता है। ऐसा होने से रोकने के लिए, जन्म दर पर उनके सुझावों को किसी खास समूह के लोगों के खिलाफ नहीं समझना चाहिए। मेरी राय में, अगर हम भागवत जी के सुझावों को सही नजरिए से लें, बिना किसी डर या शक के उनके इरादों पर ध्यान दें, तो भारत ज्यादा एकजुट और मजबूत होगा। जैसा कि मैं देखता हूं, घर वापसी पर उन्होंने जो कहा, उसमें किसी के लिए या किसी धर्म के लिए कोई बुरी भावना नहीं है।

लॉन्ग ड्रेस बनी मलाइका अरोड़ा के लिए मुसीबत! चलना हुआ मुश्किल

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहना अच्छे से जानती हैं। 52 साल की उम्र में मलाइका हर बार अपने लुक से फैंस को चौंका देती हैं और बोल्डनेस से सबका ध्यान अपनी ओर खींचती नजर आती हैं। वहीं, हाल ही में फिर मलाइका अपने अलग स्टाइल से फैंस का ध्यान खींचती नजर आईं, लेकिन इस दौरान उनका

> उनके आस पास के लोग भी उनकी ड्रेस और कहीं गिर न जाने को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। बता दें, हाल ही में मलाइका अरोड़ा का एक फोटो वायरल हुआ था।

चलना मुश्किल हो गया। एक्ट्रेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मलाइका अरोड़ा ने ग्रीन कलर की काफी लंबी ड्रेस पहनी है। यह ड्रेस इतनी लंबी है कि वह ढंग से चल भी नहीं पा रही है। जब वह चलती हैं तो यह उनके पैरों के नीचे आ जाती है। उन्हें सीढ़ी उतरने के लिए एक आदमी का सहारा लेना पड़ रहा है। उनके आस पास के लोग भी उनकी ड्रेस और कहीं गिर न जाने को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। बता दें, हाल ही में मलाइका अरोड़ा का एक फोटो वायरल हुआ था। फोटो में वह हर्ष मेहता के साथ रोम के मशहूर ट्रेवी फाउंटेन पर सेल्फी ले रही थीं। इसके बाद उनके अफेयर की अटकलें शुरू हो गईं। हालांकि, अब तक न ही मलाइका और न ही हर्ष ने अपने रिश्ते की पुष्टि की है। मालूम हो, इससे पहले मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप में थीं, लेकिन साल 2024 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। वहीं, इससे भी पहले मलाइका ने साल 1998 में अरबाज खान से शादी रचाई थी। दोनों ने साल 2002 में बेटे अरहान खान का स्वागत किया था। हालांकि, कुछ सालों बाद दोनों का तलाक हो गया था।

संजय लीला भंसाली को पड़ा दिल का दौरा? निर्देशक की टीम ने अफवाहों को सिरे से किया खारिज

सोशल मीडिया पर हाल ही में बॉलीवुड फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली को लेकर शॉकिंग खबर सुनने को मिली। कहा जा रहा है कि फिल्ममेकर को उनके बर्थडे के दिन दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एनएच हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि, कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि संजय को हार्ट अटैक आने की खबरें महज अफवाह हैं। इन सबके बीच फिल्ममेकर की टीम ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। जन्मदिन के अगले ही दिन बॉलीवुड के दिग्गज निर्माता–निर्देशक संजय लीला भंसाली को लेकर आज एक खबर आई कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। इसके बाद निर्देशक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स की देख–रेख में उनका इलाज किया जा रहा है। संजय लीला भंसाली के हार्ट अटैक की खबरें सोशल मीडिया पर फैलने के बाद उनकी टीम ने प्रतिक्रिया दी है और इन अफवाहों पर विराम लगाया है। टीम के मुताबिक, भंसाली बिल्कुल ठीक हैं और अस्पताल में भर्ती होने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। कृपया उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की अफवाह से बचें। इससे पहले बताया गया था कि संजय लीला भंसाली 24 फरवरी को अपनी 63वां जन्मदिन मना रहे थे कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया, लेकिन अब उनकी टीम ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है।

द केरल स्टोरी 2 के मेकर्स को झटका, रिलीज से एक दिन पहले केरल हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 15 दिन के लिए टली फिल्म

केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म श्द केरल स्टोरी 2–गोज बियॉन्डश की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म केरल स्टोरी 2 की रिलीज पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देते हुए सोच–समझकर काम नहीं लिया। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर यह आदेश दिया। फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि फिल्म से सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, यह पक्का करने के लिए बनाई गई गाइडलाइंस का सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने पालन नहीं किया। हाईकोर्ट में दायर याचिकओं में श्द केरल स्टोरी 2श के मेकर्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (ब्वथ्ब्) से मिले सर्टिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में दावा किया गया कि फिल्म में केरल को गलत तरीके से दिखाया गया। इससे कानून–व्यवस्था बिगड़ सकती है। फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली याचिकाओं में, याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्म का टाइटल और प्रमोशनल मटीरियल दोनों ही केरल को गलत तरीके से दिखाते हैं। उनमें ऐसे थीम हैं जो भाईचारा बिगाड़ सकते हैं और कानून–व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ सकते हैं। एक याचिका में टाइटल से केरल हटाने के लिए भी निर्देश देने की मांग की गई थी। विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन में बनी फिल्म द केरल स्टोरी 2 को ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर कड़े रिएक्शन मिले। फिल्म के एक सीन पर यूजर्स ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इसमें जबरदस्ती एक महिला को प्रतिबंधित मांस खिलाया जाता है। मंगलवार को केरल हाई कोर्ट ने फिल्म देखने की इच्छा जताई थी। मेकर्स ने अदालत से कहा कि द केरल स्टोरी 2 ने सीबीएफसी से स्वीकृति ली है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सीबीएफसी की तरफ से स्वीकृति दिए जाने पर भी सवाल उठाए हैं।

रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में चौंकाने वाला खुलासा, तिहाड़ और आर्थर रोड जेल से रची गई हमले की साजिश

मशहूर बॉलीवुड फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर पिछले दिनों फायरिंग की घटना हुई थी। वहीं, अब इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हाल ही में मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि दिल्ली की तिहाड़ और मुंबई की आर्थर रोड जेल से इस पूरी वारदात की साजिश रची गई थी। हाल ही में पूछताछ के दौरान हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि इस साजिश के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों से जुड़े हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने की मुख्य जिम्मेदारी श्आगरा मॉड्यूलश को दी गई थी। इस मॉड्यूल में शूटर दीपक चंद्रा मुख्य भूमिका में था। जांच में खुलासा हुआ कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस गैंग के सदस्य गोलू पंडित ने इस पूरे मॉड्यूल का कोऑर्डिनेशन किया था। गोलू पंडित और शुभम लोनकर के बीच पुराना परिचय था, जिसके चलते शुभम ने गोलू को फायरिंग के लिए नए लड़कों की भर्ती करने का काम सौंपा था।शूटरों की भर्ती की प्रक्रिया काफी सोची–समझी थी। तिहाड़ में बंद गोलू पंडित ने विष्णु कुशवाहा नाम के शख्स से संपर्क किया, जिसने आगे चलकर शूटर दीपक और अन्य लड़कों को इस अपराध के लिए तैयार किया। बाद में शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई सीधे दीपक और उसके साथियों के संपर्क में आए और उन्हें काम के बदले मोटी रकम देने का लालच दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि शूटरों की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ही गोलू पंडित जमानत पर बाहर आ गया था। अब मुंबई पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। वहीं, इस वारदात के लिए वाहन और हथियारों की व्यवस्था 'पुणे मॉड्यूल' के जरिए की गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि इसका संचालन शुभम लोनकर का भाई प्रवीण लोनकर कर रहा था, जो इस समय आर्थर रोड जेल में बंद है। उस पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी आरोप हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि जेल में रहते हुए ही वह इस हमले से जुड़ी लॉजिस्टिक गतिविधियों को संभाल रहा था। अब मुंबई पुलिस प्रवीण लोनकर की रिमांड लेने की तैयारी में है, ताकि पूछताछ के जरिए इस साजिश के और पहलुओं को उजागर किया जा सके। यह मामला इस ओर इशारा करता है कि जेल के भीतर से भी संगठित अपराध किस तरह सक्रिय है और फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों को निशाना बनाने की कोशिशें जारी हैं।

मार्टिन शॉर्ट की बेटी कैथरीन शॉर्ट ने किया सुसाइड, घर पर खुद को गोली मार समाप्त की जीवन लीला

मशहूर हॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन मार्टिन शॉर्ट की बेटी को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है। एक्टर की 42 वर्षीय बेटी कैथरीन शॉर्ट अपने लॉस एंजिलिस वाले घर पर मृत पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि कैथरीन ने सुसाइड किया है। टीएमजे के मुताबिक, कैथरीन शॉर्ट ने सोमवार रात हॉलीवुड हिल्स में अपने घर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार शाम करीब 6 बजे हॉलीवुड हिल्स स्थित उनके घर पर लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट के आपातकालीन क्रू को बुलाया गया था। इसके बाद लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग (एलएपीडी) और आपातकालीन टीमें तुरंत पहुंचीं और टीम ने जांच पड़ताल की और बताया कि कैथरीन की मौत हो चुकी है। बाद में उन्होंने इस खबर की कि कैथरीन ने गोली मारकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। कैथरीन की मौत के बाद उनके पिता मार्टिन शॉर्ट ने एक स्टेटमेंट जारी कर उनकी मौत की पुष्टि की। उन्होंने कहा, बेहद गहरे दुख के साथ हम कैथरीन हार्टले शॉर्ट के निधन की पुष्टि करते हैं। शॉर्ट परिवार इस क्षति से पूरी तरह टूट गया है और आप सभी से निवेदन है कि, इस कठिन समय में हमें थोड़ी प्राइवेसी दीजिए। कैथरीन सभी की प्रिय थीं और उन्हें उनके खुशनुमा अंदाज के लिए हमेशा याद किया जाएगा जो उन्होंने इस दुनिया में बिखेरी। बता दें, कैथरीन के पिता मार्टिन शॉर्ट भले ही एक्टिंग की दुनिया में एक जाने–माने स्टार हैं, लेकिन कैथरीन का इससे कोई वास्ता नहीं रहा। वह अपना खुद का एक क्लीनिक भी चलाती थीं और साथ ही अमी हेल्थ में पार्ट टाइम जॉब करती थीं। हालांकि, दुनिया को मानसिक ज्ञान देने वाली ने कैथरीन की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया है।

सूट की स्लीव्स चौड़ी होने पर टेलर से बनवाएं ऐसी डिजाइंस, मिलेगा परफेक्ट लुक

जब भी हम मार्केट से सूट लेते हैं या फिर टेलर से इसको सिलवाते हैं, तो सूट की डिजाइन को अपनी पसंद के हिसाब से बनवाते हैं। जिससे कि जब हम वह सूट पहनें तो वह परफेक्ट लगे। लेकिन कई बार गलत फिटिंग की वजह से बाजू चौड़ी हो जाती है। जो देखने में बेहद खराब लगती है। ऐसे में जरूरी नहीं है कि आप सूट पहनना ही छोड़ दें। बल्कि सूट की स्लीव्स को सही करवाने के लिए आप कुछ अलग डिजाइन को क्रिएट करवा सकती हैं। जिससे कि जब आप इन सूट्स को पहनें तो यह आप पर परफेक्ट लगें। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप सूट में किस तरह की स्लीव्स ट्राई कर सकती हैं।

डोरी सूट स्लीव्स

अगर आपके सूट की बाजू चौड़ी हो गई है, तो आप टेलर से कहकर इसमें डोरी लगवा सकती हैं। इससे जब आप डोरी को टाइट करके बाधेंगी, तो आपकी स्लीव्स बिलकुल फिट हो जाएगी। आप चाहें तो इसमें एक अच्छा सा टेस्ल लगा सकती हैं। वहीं बाजू पर कलर कॉन्ट्रास्ट करके बटन को फिक्स करवा सकती हैं। इस तरह से आपकी स्लीव्स सही हो जाएगी।

फ्लेयर डिजाइन

अगर सूट में आपकी बाजू नीचे से चौड़ी नजर आ रही है। तो इसमें कट देकर फ्लेयर डिजाइन क्रिएट करवाकर इस पर फिक्स कर सकती हैं। आजकल इस तरह की स्लीव्स वाले काफी डिजाइन चल रहे हैं और काफी अच्छे लगते हैं। ऐसे में आपको सूट में यह डिजाइन जरूर ट्राई करनी चाहिए।

चूड़ीदार स्लीव्स

अगर आपने अपने सूट में फुल स्लीव्स बनवाई है और बाजू की फिटिंग सही नहीं है। तो आप इसमें प्लीट्स डलवा सकती हैं। इससे सूट के बाजू में चूड़ियां बन जाएंगी, जो आजकल काफी अच्छी लगती है। वहीं इस तरीके से सूट की फिटिंग भी परफेक्ट हो जाएगी और आपको कुछ नया ट्राई करने का मौका मिलेगा।

पुराने हो गए हैं हैंगर तो फेंकने की जगह ऐसे करें इस्तेमाल

अपनी अलमारी में कपड़ों को सरीखे से लगाने के लिए हम सभी हैंगर का इस्तेमाल करते हैं। हैंगर अमूमन लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन एक समय के बाद वह मुड़ जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं। इस स्थिति में हम सभी उन हैंगरों को यूं ही बाहर फेंक देते हैं। जबकि ये पुराने हैंगर भी आपके बेहद काम आ सकते हैं। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको इन पुराने हैंगरों को इस्तेमाल करने के कुछ अमेजिंग आइडियाज आपके साथ शेयर कर रहे हैं–

बनाएं ज्वैलरी आर्गेनाइजर

अगर आपके पास घर में पुराने हैंगर हैं तो आप उन्हें बतौर ज्वैलरी आर्गेनाइजर इस्तेमाल कर सकती हैं। आप हुक बनाने के लिए हैंगर को मोड़ सकते हैं और उसमें नेकपीस से लेकर ब्रेसलेट व इयररिंग्स आदि आसानी से हैंग कर सकते हैं।

स्कार्फ होल्डर

अक्सर हम सभी कई अलग–अलग कलर के स्कार्फ को अपने लुक का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन वह यूं ही इधर–उधर फैले रहते हैं। ऐसे में स्कार्फ को आसानी से आर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए आप हैंगर के चारों ओर उसे रैप करें। इस तरह आप एक हैंगर में कई स्कार्फ को आसानी से हैंग कर सकते हैं।

बेल्ट आर्गेनाइजर

पुराने हैंगर को बतौर बेल्ट आर्गेनाइजर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप हैंगर हुक पर बेल्ट लटकाएं, जिससे आपकी अलमारी अधिक आर्गेनाइज्ड नजर आए।

बनाएं प्लांट होल्डर

घर में रखे छोटे प्लांट्स व पॉट्स को रखने के लिए भी आप हैंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप पुराने हैंगर को मोड़कर गोल शेप दें। अब आप इसमें आसानी से पॉट को रख सकते हैं। वहीं हैंगर का हुक प्लांट को टांगने में काम आएगा।

हैंग करें स्टेशनरी आइटम्स

अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जो बार–बार अपना स्टेशनरी आइटम इधर–उधर बिखेर देते हैं तो ऐसे में पुराने हैंगर की मदद से आप इस सामान को आर्गेनाइज करें। इस हैंगर में आप बच्चों की कलर टेप से लेकर रिबन व अन्य आइटम्स को आसानी से आर्गेनाइज्ड तरीके से हैंग कर सकते हैं।

गरीबी और बीमारी होगी दूर, बस राशि अनुसार होलिका दहन में अर्पित करें ये लकड़ी

सनातन धर्म में होलिका दहन का खास महत्व माना जाता है। यह पर्व केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नहीं है, बल्कि नकारात्मक शक्तियों और अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाने का भी अवसर होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार विशेष लकड़ी होलिका में अर्पित करे, तो उसे रुके हुए कार्यों में सफलता, आर्थिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। प्रत्येक राशि के लिए अलग लकड़ी शुभ मानी जाती है और इसका सही चयन जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करता है।

राशि अनुसार लकड़ी और लाभ

मेष और वृश्चिक

मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए होलिका दहन में खैर या खादिर की लकड़ी अर्पित करना शुभ माना जाता है। इन राशियों पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है, जो साहस और ऊर्जा प्रदान करता है। खैर की लकड़ी अग्नि तत्व से जुड़ी मानी जाती है और इसे अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, जिससे रुके हुए कार्य पूरे होने में मदद मिलती है।

वृष और तुला

वृष और तुला राशि के जातकों के लिए होलिका दहन में गूलर की लकड़ी अर्पित करना शुभ माना जाता है। इन राशियों पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, जो आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सुख और वैभव का प्रतीक है। गूलर का उपयोग करने से जीवन में समृद्धि बढ़ती है और परिवार में खुशहाली आती है।

मिथुन और कन्या

मिथुन और कन्या राशि के जातकों के लिए होलिका दहन में अपामार्ग की लकड़ी अर्पित करना शुभ होता है। इन राशियों पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है, जो बुद्धि और वाणी में निपुणता का प्रतीक है। अपामार्ग अर्पित करने से करियर और व्यापार में नए अवसर प्राप्त होते हैं और मानसिक उलझनें दूर होती हैं।

धनु और मीन

धनु और मीन राशि के जातकों के लिए होलिका दहन में पीपल की लकड़ी अर्पित करना शुभ माना जाता है। इन राशियों पर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव होता है, जो ज्ञान और धर्म में प्रगति का संकेत देता है। पीपल अर्पित करने से गुरु दोष शांत होता है और भाग्य में वृद्धि होती है।

मकर और कुंभ

मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए होलिका दहन में शमी की लकड़ी अर्पित करना शुभ माना जाता है। इन राशियों पर शनि ग्रह का प्रभाव रहता है। शमी अर्पित करने से कार्य में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और न्याय संबंधी मामलों में राहत मिलती है।

कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए होलिका दहन में पलाश की लकड़ी अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस राशि पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। पलाश अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है।

सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए होलिका दहन में मदार की लकड़ी अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस राशि पर सूर्य का प्रभाव होता है। मदार अर्पित करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।

होलिका दहन में शुभ उपाय

लकड़ी को होलिका में अर्पित करते समय श्रद्धा भाव रखें।

सात फेरे लेते समय लकड़ी अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है।

सही लकड़ी का चयन करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ज्योतिषी के अनुसार, होलिका दहन केवल उत्सव नहीं है, बल्कि यह जीवन में रुके कार्यों में सफलता और मानसिक संतुलन पाने का अवसर भी है। सही लकड़ी का चयन करके आप नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं और अपने कार्यों में सफलता पा सकते हैं। इस होलिका दहन पर अपनी राशि के अनुसार लकड़ी का चयन करना न केवल पारंपरिक मान्यता है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक बदलाव और मानसिक शांति का मार्ग भी खोलता है। इस बार होलिका जलाते समय अपनी राशि के अनुसार लकड़ी चुनें और लाभ उठाएं।

दवाओं से नहीं इन 5 सुपर फूड से करें शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी

शरीर को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें सारे पोषक तत्व मिलें, वरना बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है। कैल्शियम खासकर के तो बहुत जरूरी है। इससे हड्डियों और दांत मजबूत रहते हैं। वहीं बल्ड सर्कुलेशन, मसल्स बनाने और दिमाग के बेहतर दंग से काम करने के लिए कैल्शियम की सख्त जरूरत होती है। कई लोग शरीर में कैल्शियम की कमी की पूरा करने के लिए दवाओं का सहारा लेते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बस अपने डाइट में ये फूड्स शामिल कर लें।

हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियां पोषक तत्वों का खजाना होती हैं। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप अपने डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, बीन्स शामिल कर सकते हैं।

चना

एक्सपर्ट्स की मानें तो 100 ग्राम चने में लगभग 150 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। चना शाकाहारी प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। इसमें आयरन, कॉपर, फोलेट और फॉस्फोरस से भरपूर होता है। आप अपनी डाइट में चने को कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही टेस्टी डिशेज भी खा सकते हैं।

भिंडी

इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, मैग्नीशियम, फोलेट और विटामिन–बी 6 जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। कैल्शियम की कमी को भी पूरा करने के लिए आप भिंडी को अपने डाइट में शामिल करें। एक्सपर्ट्स की मानें तो 100 ग्राम भिंडी में 86 मिलीग्राम कैल्शियम होता है।

सोयाबीन

सोयाबीन को शाकाहारी के लिए प्रोटीन के अलावा कैल्शियन का बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। इसमें कैल्शियम के अलावा आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है।

बादाम

बादाम दिमाग तो तेज करता ही है साथ में शरीर में कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। इसके अलावा ये ओमेगा– 3 फैटी एसिड, आयरन, फाइबर और विटामिन–के से भरपूर होता है। रात में बादाम को पानी में भिगो दें, अगले दिन सुबह इनका छिलका उतारकर खा सकते हैं।

सुबह खाली पेट जरूर खाएं ये 1 फल, पाचन रहेगा दुरुस्त और पेट में सड़ रही गंदगी होगी साफ

केला एक ऐसा फल है जो सालभर आसानी से उपलब्ध रहता है और कीमत में भी किफायती होता है। यही वजह है कि इसे सबसे ज्यादा खाए जाने वाले फलों में गिना जाता है। पोषण के मामले में भी केला काफी समृद्ध होता है। इसमें पोटैशियम, डायटरी फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी6, मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। कई लोग सुबह नाश्ते में फल खाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या केला खाली पेट खाना फायदेमंद है? आइए आसान भाषा में जानते हैं इसके फायदे।

पाचन शक्ति को करता है मजबूत

सुबह खाली पेट केला खाने से पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। केले में भरपूर मात्रा में डायटरी फाइबर होता है, जो आंतों की सफाई में मदद करता है। यह मल को मुलायम बनाकर उसे आसानी से बाहर निकालने में सहायक होता है। अगर आपको कब्ज, गैस या पेट साफ न होने की समस्या रहती है, तो रोज सुबह एक केला खाना फायदेमंद हो सकता है। इससे पेट हल्का महसूस होता है और पाचन प्रक्रिया सुचारु रहती है।

दिनभर देता है भरपूर ऊर्जा

केला प्राकृतिक ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। सुबह खाली पेट केला खाने से आप दिनभर एक्टिव और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। यही वजह है कि खिलाड़ी और जिम जाने वाले लोग भी केला खाना पसंद करते हैं।

इम्यूनिटी को करता है मजबूत

केले में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन सी सफेद रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है, जो संक्रमण से लड़ने का काम करती हैं। साथ ही यह शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से भी बचाता है।

दिल को रखता है स्वस्थ

दिल की सेहत के लिए पोटैशियम बहुत जरूरी मिनरल है, और केला पोटैशियम का अच्छा स्रोत है। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। नियमित रूप से केला खाने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम हो सकता है और हृदय रोगों की संभावना भी घटती है। इसलिए हार्ट हेल्थ के लिए भी केला फायदेमंद माना जाता है।

सूजन और मांसपेशियों के दर्द में राहत

केला शरीर में होने वाली सूजन (इंफ्लेमेशन) को कम करने में मदद कर सकता है। जिन लोगों को मसल्स क्रैम्प्स यानी मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या होती है, उनके लिए केला लाभकारी हो सकता है। इसमें मौजूद पोटैशियम मांसपेशियों को रिलैक्स रखने में मदद करता है और ऐंठन की समस्या को कम कर सकता है।

ध्यान रखने वाली बात

हालांकि केला सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन डायबिटीज या किसी खास बीमारी से पीड़ित लोगों को डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए।

संक्षिप्त

हरे निशान पर खुला भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 303 अंक चढ़ा

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को हरे निशान पर खुला। आईटी शेयरों में खरीदारी और विदेशी फंडों के नए प्रवाह के चलते गुरुवार को शुरुआती कारोबार में इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी आई। अमेरिकी बाजारों में आई तेजी ने भी शुरुआती कारोबार के दौरान बेंचमार्क सूचकांकों को बढ़त हासिल करने में मदद की। शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे बढ़कर 90.85 पर पहुंचा। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 303 अंक चढ़कर 82,579.16 पर पहुंच गया। वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 85.1 अंक बढ़कर 25,567.60 पर पहुंच गया। सेंसेक्स पैक में, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, एचसीएल टेक, इटरनल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और मारुति सबसे बड़े लाभ कमाने वालों में शामिल थे। इंटरग्लोब एविएशन, अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पिछड़ने वालों में शामिल थे। ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ टेक फर्म एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा, पिछले सत्र में एफपीआई (2,991 करोड़ रुपये) और डीआईआई (5,118 करोड़ रुपये) दोनों द्वारा की गई मजबूत खरीदारी से निवेशकों को अतिरिक्त भरोसा मिलने की संभावना है। घरेलू बुनियादी बातें स्थिर बनी हुई हैं, और चल रहे सेक्टोरल रोटेशन से सूचकांकों को उच्च स्तर पर आवधिक लाभ–बुकिंग को अवशोषित करने में मदद मिल रही है। एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 सकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे, जबकि शंघाई का एसएसई कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स नीचे कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.25 प्रतिशत बढ़कर 71.03 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गया। बाजार विनिमय आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 2,991.64 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी 5,118.57 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। बुधवार को सेंसेक्स 50.15 अंक या 0.06 प्रतिशत बढ़कर 82,276.07 पर बंद हुआ। निफ्टी 57.85 अंक या 0.23 प्रतिशत बढ़कर 25,482.50 पर स्थिर हुआ।

पर्यटन को विकास का इंजन बनाने की तैयारी, जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ाकर 10 फीसदी करने का लक्ष्य

नई दिल्ली,एजेसी। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पर्यटन अब राष्ट्रीय विकास का एक अहम स्तंभ बन चुका है। उन्होंने सरकार के उस विजन को रेखांकित किया, जिसके तहत पर्यटन क्षेत्र का जीडीपी में योगदान मौजूदा 6: से बढ़ाकर 10: तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। शेखावत ने यह बात नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में आयोजित साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज के 33वें संस्करण में कही। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा कि पर्यटन न केवल आर्थिक वृद्धि को गति देता है, बल्कि रोजगार सृजन, सांस्कृतिक आदान–प्रदान और क्षेत्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने उद्योग से जुड़े सभी हितधारकों के साथ मिलकर इस क्षेत्र को और मजबूत करने पर जोर दिया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता भी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में देश–विदेश से आए पर्यटन और यात्रा उद्योग के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने भाग लिया। कनाडा ने भारत के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की इच्छा जताते हुए खुद को महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति में एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार बताया है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा के वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल हेड तुषार हांडेकर ने कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के संदर्भ में कहा कि दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत व्यापारिक संबंध मौजूद हैं और इस दौरे से द्विपक्षीय व्यापार को और गति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि EDC के दृष्टिकोण से भारत–कनाडा व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाने और व्यापार प्रवाह को अधिक सुगम बनाने पर जोर रहेगा। हांडेकर के अनुसार, भविष्य में मुक्त व्यापार समझौता होने की भी संभावना है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार को और सहज और तेज बनाएगा। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि कनाडा, भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति में एक विश्वसनीय और दीर्घकालिक साझेदार के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहता है।

अर्श से फर्श पर श्रीलंका क्रिकेट! पिछले पांच संस्करण में नॉकआउट स्टेज में भी नहीं पहुंच पाई टीम

कोलंबो,एजेंसी। मेजबान श्रीलंका टी20 विश्वकप 2026 के सुपर–8 राउंड से बाहर होने वाली पहली टीम बनी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 61 रन की बड़ी हार ने सेमीफाइनल में पहुंचने के उसके सभी रास्तों को बंद कर दिया। ग्रुप स्टेज में श्रीलंका का प्रदर्शन शानदार रहा था। उसने आयरलैंड, ओमान और फिर ऑस्ट्रेलिया को हराकर दबदबा बनाया। हालांकि, पिछले तीन मैचों में टीम जीत की पटरी से उतर गई। जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई। 2014 टी20 विश्वकप के बाद से श्रीलंका का सफर इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं रहा है। पिछले पांच संस्करणों से उसका नॉकआउट या सेमीफाइनल स्टेज में पहुंचने का सूखा जारी है। 2014 टी20 विश्वकप में दिनेश चांदीमल और लसिथ मलिंगा की अगुआई में महेला जयवर्धने और कुमार संगकारा जैसे दिग्गजों से सजी टीम चैंपियन बनी थी। इसके बाद से टीम का सफर इस टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं रहा है। इसके बाद लगातार पांच बार श्रीलंकाई टीम सेमीफाइनल या नॉकआउट में पहुंचने से पहले ही बाहर हुई है।

2016 टी20 विश्वकप में श्रीलंका को सुपर–10 स्टेज से बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। उसने सुपर–10 में चार में से सिर्फ एक मैच जीता था। तब श्रीलंकाई टीम वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के साथ एक सुपर–10 ग्रुप में थी। 2021 टी20 विश्वकप में श्रीलंकाई टीम सुपर–12 राउंड से बाहर हो गई थी। उसने सुपर–12 राउंड में पांच में से सिर्फ दो मैच जीते थे। उसके ग्रुप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, द. अफ्रीका, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश जैसी टीमें थीं। 2022 टी20 विश्वकप में भी श्रीलंकाई टीम सुपर–12 राउंड से बाहर हो गई थी। उसने सुपर–12 में पांच में से दो मैच जीते। उसके ग्रुप में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और अफगानिस्तान जैसी टीमें थीं। 2024 टी20 विश्वकप में तो श्रीलंकाई टीम पहले राउंड यानी ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। ग्रुप स्टेज में उसने चार में से एक मैच में

जीत हासिल की थी। उसके ग्रुप में दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, नीदरलैंड और नेपाल जैसी टीमें थीं। 2026 में 2024 के मुकाबले तो प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन टीम सुपर–8 में ग्रुप स्टेज वाले प्रदर्शन को दोहराने में कामयाब नहीं हो सकी और सुपर–8 से बाहर हो गई।

बात अगर 2014 में चौंपियन बनने से पहले की करें तो भी श्रीलंका का प्रदर्शन बेहद कंसिस्टेंट रहा था। 2014 से पहले श्रीलंका की टीम चार संस्करणों में से तीन में नॉकआउट राउंड में पहुंची थी। इनमें से दो फाइनल शामिल हैं। 2007 में श्रीलंकाई टीम सुपर–8 से बाहर हुई थी। 2009 और 2012 में श्रीलंकाई टीम उपविजेता रही थी। 2010 में श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी। न्यूजीलैंड के हाथों 61 रन से हार के बाद कप्तान दासुन शनाका निराश हैं। उनका मानना है कि घरेलू दर्शकों को निराश करना वाकई बहुत शर्मनाक होता है। बुधवार को आर प्रेमदासा स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने सात विकेट खोकर 168 रन बनाए। इस पारी में कप्तान मिचेल सैंटनर (47) और कोल मैककोन्ची (नाबाद 31) के बीच 84 रन की साझेदारी हुई। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 107 रन ही बना सकी।

श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका ने कहा, घरेलू दर्शकों को निराश करना वाकई बहुत शर्मनाक होता है। वे हमेशा हमारा समर्थन करते रहे हैं। हमने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन सच कहूं तो मिचेल सेंटनर और कोल मैककोन्ची की साझेदारी शानदार रही, जिसने मैच हमसे दूर कर दिया। हमारी योजना उन्हें करीब 130 रनों पर रोकने की थी, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो हमारे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों के सामने भी उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की। इसलिए हमें उन्हें श्रेय देना होगा। उन्होंने कहा, श्बल्लेबाजों को शीर्ष क्रम में अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी। हम एक–दो खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं रह सकते। सभी बल्लेबाजों को सकारात्मक विकल्प अपनाने होंगे। अगर आप सकारात्मक खेलते हुए आउट भी होते हैं, तो डगआउट में लौटते वक्त संतोष रहता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, हमने चांस नहीं लिए। यह टी20 क्रिकेट है, यहां इरादा और आक्रामकता दिखानी ही पड़ती है। श्रीलंका खिताबी रेस से बाहर है। हालांकि, टीम 28 फरवरी को अपना अंतिम सुपर–8 मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। कप्तान ने भरोसा जताया है कि टीम शानदार अंदाज में अपने विश्व कप अभियान का समापन करेगी। दासुन शनाका ने कहा, अब एक और मैच है और हमें उसे मजबूती से खत्म करना होगा। उम्मीद है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।

जब सचिन की आंखों में दिखा गर्व और प्यार, बेटे अर्जुन से कहा– मुझे तुम पर फख्र है

नई दिल्ली,एजेंसी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के घर इस समय खुशियों का माहौल है। बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी सानिया चंदोक से होने जा रही है और इसी खुशी के मौके पर अंबानी परिवार ने तेंदुलकर परिवार को खास तौर पर आमंत्रित कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस खास मुलाकात का एक भावुक वीडियो अब मुंबई इंडियंस की ओर से जारी किया गया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।ीडियो में माहौल बेहद आत्मीय और पारिवारिक नजर आ रहा है। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाला पल तब आता है जब सचिन अपने बेटे अर्जुन की ओर देखते हुए कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व है। इन शब्दों में एक पिता का गर्व, स्नेह और विश्वास साफ झलकता है। सचिन की आवाज में भावनाएं साफ महसूस की जा सकती हैं। यह सिर्फ एक औपचारिक बधाई नहीं, बल्कि उस सफर की स्वीकृति है जो अर्जुन ने अपने दम पर तय किया है। अंबानी परिवार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दोनों परिवारों के बीच गर्मजोशी और अपनापन देखने को मिला। शादी की तैयारियों के बीच यह खास पल तेंदुलकर परिवार के लिए और भी यादगार बन गया। वीडियो में अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ अपने पिता की बात सुनते नजर आते हैं। पिता के मुंह से मुझे तुम पर गर्व हैश्सुनना किसी भी बेटे के लिए जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होता है और यही भाव इस वीडियो को खास बना देता है। सोशल मीडिया पर फैंस भी इस पल को देखकर भावुक हो गए हैं। अर्जुन की सगाई सानिया चंदोक के साथ हुई है। सानिया मुंबई के प्रसिद्ध व्यवसायी रवि घई की पोती हैं। घई परिवार हॉस्पिटेलिटी और खाद्य क्षेत्र में सुप्रसिद्ध है, जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और आइसक्रीम ब्रांड ब्रूकलिन क्रीमरी का स्वामित्व है। अर्जुन और सानिया की सगाई एक निजी कार्यक्रम में हुई जिसमें करीबी दोस्त और दोनों परिवार के सदस्य शामिल हुए थे। 25 वर्षीय अर्जुन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं, जो घरेलू क्रिकेट में गोवा का प्रतिनिधित्व करते हैं और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं। आईपीएल 2026 के लिए हुई मिनी नीलामी से पहले लखनऊ सुपरजाएंट्स ने अर्जुन को मुंबई से ट्रेड किया था।

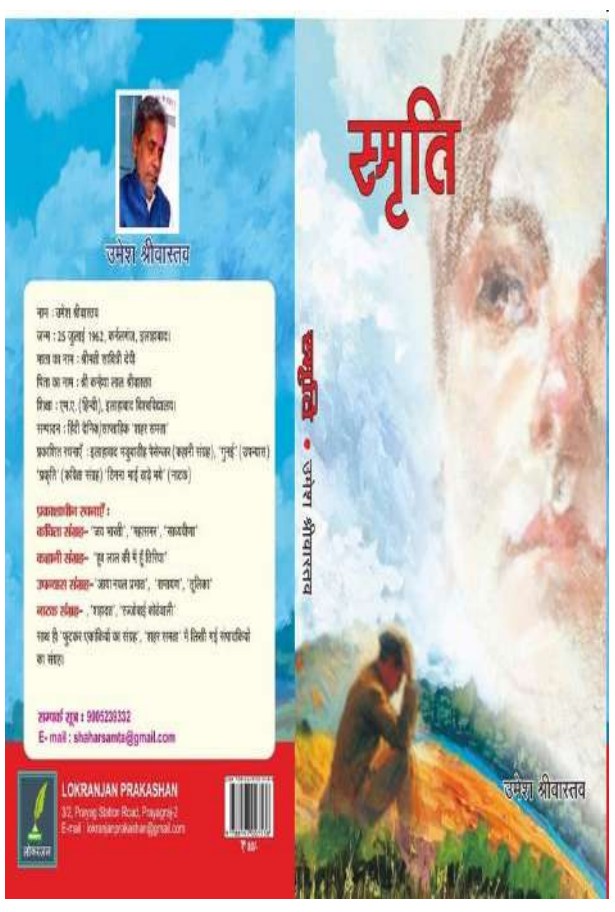

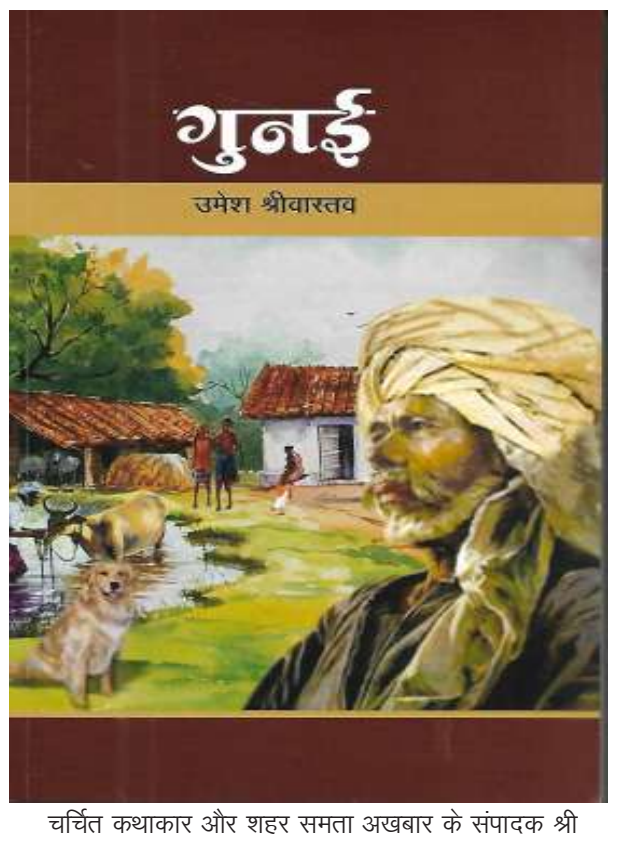

चर्चित कथाकार और शहर समता अखबार के संपादक श्री उमेश श्रीवास्तव जी का ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा बहु प्रतीक्षित

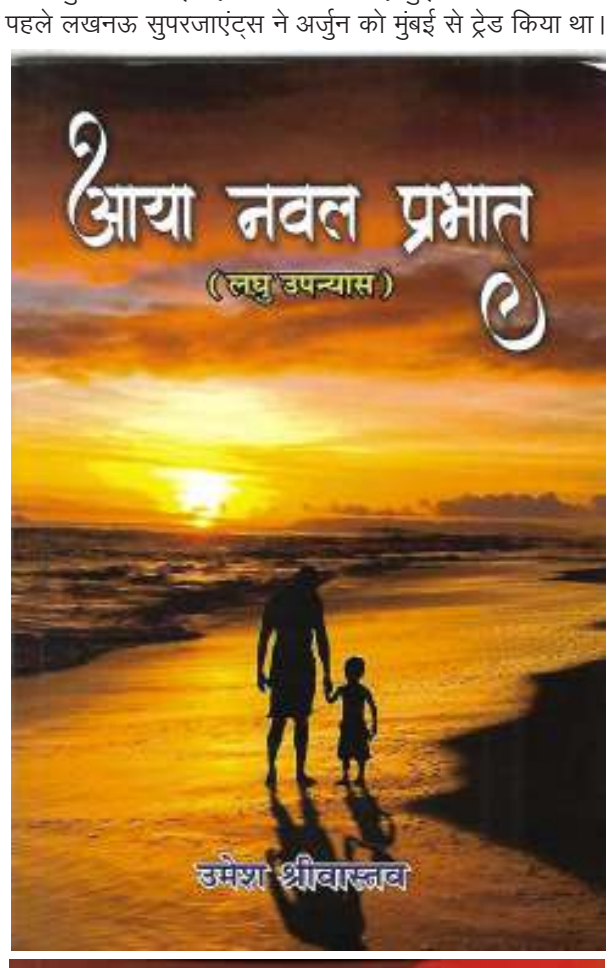

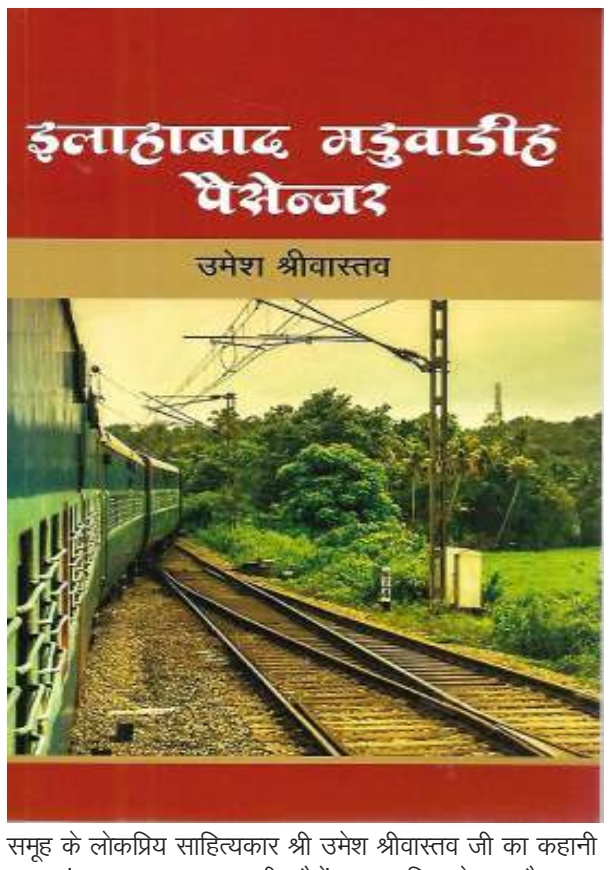

समूह के लोकप्रिय साहित्यकार श्री उमेश श्रीवास्तव जी का कहानी संग्रह इलाहाबाद मडुवाडीह पैसेंजर प्रकाशित हो गया है। उमेश श्रीवास्तव जी को बहुत बधाई एवम शुभकामना।

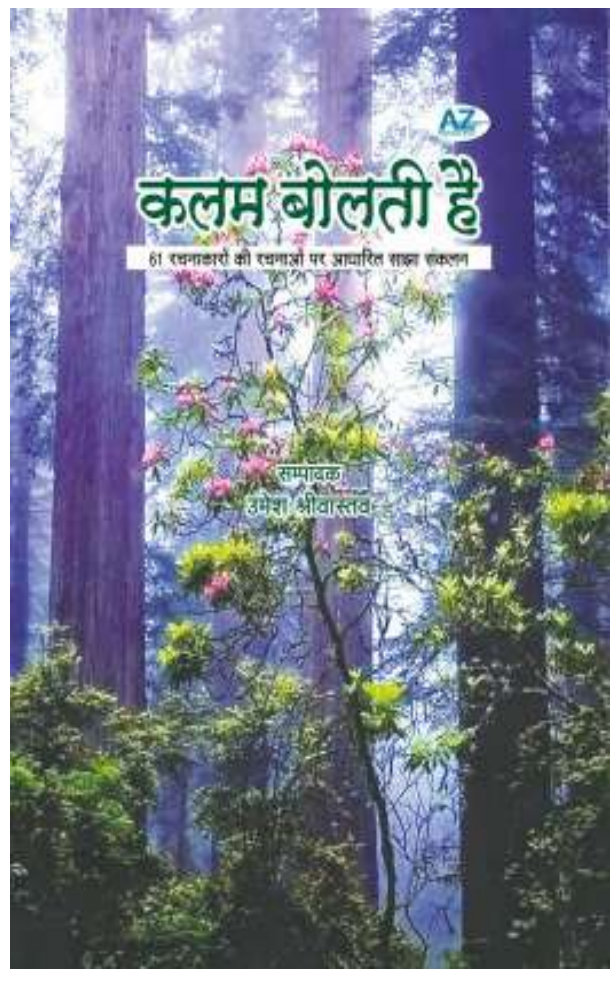

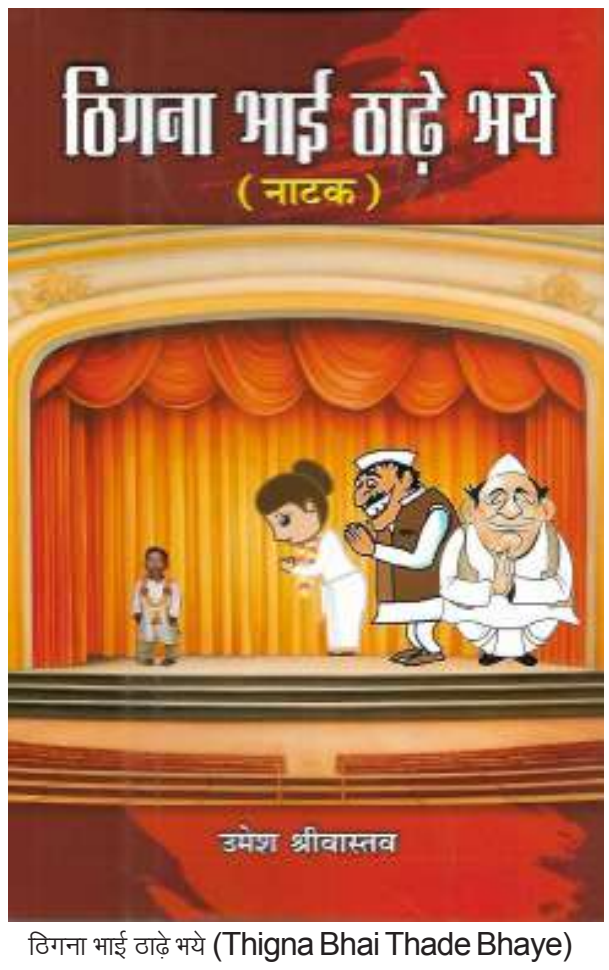

ठिगना भाई ठाढ़े भये (Thigna Bhai Thade Bhaye)

राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण को कमला हैरिस ने झूठा बताया, अमेरिकियों को गुमराह करने का लगाया आरोप

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे झूठ से भरा हुआ बताया। इसके साथ ही उन पर अर्थव्यवस्था, मतदान के अधिकार और ईरान के मुद्दों पर अमेरिकियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। ट्रंप के भाषण के एक दिन बाद, हैरिस ने बुधवार (स्थानीय समय) को अपने सबस्टैक शो द पारनास पर्सपेक्टिव के होस्ट आरोन पारनास को बताया कि उन्होंने भाषण देखा और पाया कि यह आम परिवारों के सामने आने वाली वास्तविकताओं से अलग था। उन्होंने कहा "मैंने इसे देखा। यह झूठ से भरा हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की स्थिति मजबूत है। हैरिस ने कहा, बिल्कुल नहीं ष्मैं आपको बता दूं... बहुत से लोग बढ़ती कीमतों, महंगी स्वास्थ्य सेवाओं और महंगे आवास के बोझ तले दबे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में दक्षिणी राज्यों की अपनी यात्राओं का वर्णन किया। उन्होंने मिसिसिपी में एक ऐसी मां से मिलने का किस्सा सुनाया, जिसका चार लोगों के लिए साप्ताहिक किराने का बजट मात्र 150 डॉलर था। हैरिस ने कहा, ष्कार्ट में जो कुछ भी था, वह उसके बच्चों के लिए ही था,ष और आगे बताया कि उस मां ने उनसे कहा कि जो कुछ भी उनके बच्चे नहीं खाएंगे, वह खुद खा लेगी। ष्वह बोतलबंद पानी लेने के लिए चलकर गई क्योंकि वह नल का पानी नहीं पी सकती, क्योंकि पानी भूरा और जहरीला है। यही है अमेरिका। हैरिस ने प्रस्तावित खर्च प्राथमिकताओं की भी आलोचना की। उन्होंने पूछा, ष्जब आप मेडिकेड में 1 ट्रिलियन डॉलर की कटौती करते हैं, तो इससे किसके लिए आवाज उठती है? वहीं दूसरी ओर, अमेरिका के सबसे अमीर लोगों के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर की टैक्स कटौती की जा रही है। यही हमारे देश में अभी हो रहा है।ष मतदान के अधिकारों के मुद्दे पर, हैरिस ने सेव एक्ट का कड़ा विरोध किया, जिसे ट्रंप ने कांग्रेस से पारित करने का आग्रह किया था। उन्होंने तर्क दिया कि इस उपाय के तहत लोगों को मतदान के लिए पंजीकरण कराने हेतु जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं, उन्होंने दावा किया कि लगभग 40 प्रतिशत अमेरिकियों के पास ये दस्तावेज नहीं हैं विदेश नीति पर बात करते हुए, हैरिस ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने पहले दावा किया था कि उन्होंने उनके कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इसे पूरी तरह से बकवास बताया। उन्होंने कहा कि अब वह इस क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों को भेज रहे हैं, जिससे यह बहुत संभव है कि अमेरिकी पुरुषों और महिलाओं को युद्ध में तैनात किया जाएगा।ष हैरिस ने आगे कहा, "अमेरिकी जनता एक और युद्ध नहीं चाहती और न ही वे अपने बेटों और बेटियों को ऐसी कार्रवाई शुरू करने के लिए भेजना चाहते हैं जिसे टाला जा सकता है और जो कि संभव भी है।" स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को दिया जाने वाला वार्षिक भाषण है, जिसमें विधायी प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। देश की स्थिति का आकलन किया जाता है।

यह अक्सर चुनावों से पहले घरेलू और विदेश नीति संबंधी बहसों की दिशा तय करता है। 2026 के मध्यावधि चुनाव कांग्रेस पर किसका नियंत्रण होगा, यह तय करेंगे। इन्हें व्यापक रूप से मौजूदा राष्ट्रपति के एजेंडे पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जाता है और ये अमेरिकी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नीति की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

संक्षिप्त

क्यूबा की फायरिंग से बढ़ा तनाव, अमेरिका में रजिस्टर्ड नाव पर गोलीबारी से चार की मौत, घुसपैठ का आरोप

हवाना (क्यूबा),एजेंसी। कैरिबियाई सागर में स्थित द्वीपीय देश क्यूबा और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। यह तनाव बुधवार (25 फरवरी) देर रात फ्लोरिडा से आ रही एक नाव पर गोलीबारी की घटना के बाद हुआ है। क्यूबा सरकार के मुताबिक फ्लोरिडा से आ रही एक नाव ने उसके सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप झड़प शुरू हुई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। क्यूबा सरकार ने बुधवार देर रात कहा कि उसके सैनिकों पर गोली चलाने वाली नाव में सवार 10 यात्री अमेरिका में रहने वाले सशस्त्र क्यूबाई नागरिक थे, जो द्वीप में घुसपैठ करने और आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। यह प्रतिक्रिया क्यूबा द्वारा यह कहने के कुछ घंटों बाद आई है कि उसके सैनिकों ने फ्लोरिडा में पंजीकृत एक स्पीड बोट पर सवार चार लोगों को मार डाला और छह अन्य को घायल कर दिया, जो क्यूबा के जलक्षेत्र में प्रवेश कर गई थी और उसने पहले सैनिकों पर गोलीबारी की थी, जिसमें एक क्यूबा अधिकारी घायल हो गया था। क्यूबा सरकार ने कहा कि नाव में सवार 10 लोगों में से अधिकांश का श्आपराधिक और हिंसक गतिविधियों का ज्ञात इतिहास हैश। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इससे पहले पत्रकारों को बताया था कि उन्हें इस घटना की जानकारी है और अमेरिका अब यह निर्धारित करने के लिए अपनी जानकारी जुटा रहा है कि पीड़ित अमेरिकी नागरिक थे या स्थायी निवासी। रुबियो ने सेंट किट्स के बासेटेरे हवाई अड्डे पर कहा कि अमेरिकी सरकार के कई अलग–अलग विभाग इस कहानी के उन पहलुओं की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें अभी तक नहीं बताए गए हैं।

इस्राइल में फलस्तीनियों के मुद्दे उठाएं पीएम मोदी, ईरानी विदेश मंत्री ने भारत से संबंधों पर दिया ये बयान

तेहरान, एजेंसी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने गाजा में इस्राइल की सैन्य कार्रवाई की निंदा की है और पीएम मोदी से अपील की है कि वे इस्राइल दौरे पर फलस्तीनियों के अधिकारों का मुद्दा उठाएं। पीएम मोदी दो दिवसीय दौरे पर इस्राइल में मौजूद हैं। अराघची ने आरोप लगाया कि गाजा में इस्राइल की कार्रवाई नरसंहार के बराबर है और तेहरान, इस्राइल के साथ जुड़ना ठीक नहीं समझता। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस्राइल में पीएम मोदी फलस्तीनियों और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार के मुद्दे पर भी बात करेंगे। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में अराघची ने कहा, श्दुर्भाग्यवश, इस्राइल ने पूरे गाजा को तबाह किया है। 75 हजार लोग मारे गए हैं और यह सिर्फ दावा नहीं है बल्कि तथ्य है, जिसकी पुष्टि गाजा मुद्दे पर काम करने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने की है। यह एक नरसंहार है। इसलिए जाहिर है, हम ऐसे नरसंहारी शासन के साथ जुड़ना ठीक नहीं समझते। भारत में हमारे दोस्तों को खुद फैसला करना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में वे फलस्तीनियों और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार के मुद्दे पर भी ध्यान देंगे। ईरानी विदेश मंत्री ने भारत और ईरान के मजबूत संबंधों पर भी बात की और भारत को ईरान का दोस्त बताया। उन्होंने कहा, श्भारत के साथ हमारे संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। भारत ईरान का दोस्त है और हमारा रिश्ता ऐतिहासिक है। हमने हमेशा से अच्छे द्विपक्षीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध बनाए रखे हैं। हम चाहते हैं कि यह संबंध ऐसे ही बने रहें। मेरे सहयोगी मंत्री जयशंकर के साथ अच्छे संपर्क हैं और हम हमेशा अपने विचार साझा करते हैं। हमारे व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छे हैं।

ब्राजील में भीषण बाढ़ से हाहाकार, अब तक 46 लोगों की मौत, विचलित कर रहा मंजर

रियो डी जेनेरिया, एजेंसी। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में कुदरत का भयानक कहर देखने को मिल रहा है। दक्षिण–पूर्व ब्राजील में भीषण बाढ़ से लगातार मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक 46 लोगों की मौत हो गई। कई लोग लापता है, जिनको तलाश जारी है। वहीं सैकड़ों लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर है। दक्षिणपूर्वी ब्राजील के मिनास गेरैस राज्य में आई भीषण बाढ़ में लगातार मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ब्राजील के दक्षिणी भाग में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से तबाही मचने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में इस क्षेत्र में और अधिक बारिश होने की आशंका है। इधर, मिनास गेरैस राज्य में बचाव अभियान जारी है। बचाव कर्मचारी स्थिति पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बचाव अभियान पूरी तेजी से जारी है और घर व कस्बे कीचड़ और मलबे से ढके हुए हैं। इससे पहले बुधवार को ब्राजील के अग्निशमन विभाग ने मृतकों की संशोधित संख्या प्रकाशित की और बताया कि लगभग 21 लोग अभी भी लापता हैं। राज्य अग्निशमन विभाग द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार ब्राजील के दक्षिणपूर्वी राज्य मिनास गेरैस में भारी बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है।

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले से प्रकाशित समाचार पत्र को समस्त जनपदों में एवम तहसील व ब्लॉक/शहर में ब्यूरो प्रमुख, चीफ रिपोर्टर, संवाददाता, प्रतिनिधि मण्डल की अवश्यकता है जिन्हे आकर्षण वेतन और भत्ते आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

सम्पर्क सूत्र

शहर समता हिन्दी दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र

मोबाईल नम्बर 9190052 39332

919450482227

कनाडा के बदले सुर, खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या मामले में भारत के दखल को नकारा

ओटावा, एजेंसी। भारत की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक ताकत का ही असर है कि कनाडा, भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कवायद में जुटा है। यही वजह है कि कनाडा ने ये मान लिया है कि कनाडा की धरती पर होने वाले अपराधों में भारत की कोई संलिप्तता नहीं है। कनाडा के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं और कनाडा सरकार के इस कदम को दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने के तौर पर देखा जा रहा है। जो जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के अंतिम दिनों में बेहद खराब दौर में पहुंच गए थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार, कनाडा सरकार के अधिकारियों ने बताया श्अगर भारत, कनाडा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल दे रहा होता तो शायद प्रधानमंत्री कार्नी, भारत दौरे पर जाते ही नहीं।श अधिकारियों ने कहा, हमारी भारत सरकार के साथ इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। साथ ही विदेशी हस्तक्षेप से बचने के लिए हमारे पास मजबूत सुरक्षा उपाय हैं। कनाडा सरकार के अधिकारियों ने ये साफ नहीं किया कि कनाडा सरकार ने भारत को लेकर अपना रुख बदलने का फैसला कब किया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इसे लेकर पीएम मोदी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ व्यवस्थित रूप से बातचीत की गई। अधिकारियों ने कहा कि इन मुद्दों को नियमित रूप से उठाया गया और उन्हें विश्वास है कि आगे भी इस पर सार्थक चर्चा जारी रहेगी। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। कनाडा की तत्कालीन ट्रूडो सरकार ने भारत पर निज्जर की हत्या कराने का आरोप लगाया और इसे संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया था। हालांकि भारत सरकार ने कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और निज्जर की हत्या में संलिप्तता से इनकार किया। इस मामले को लेकर दोनों देशों के रिश्ते इतने बिगड़े की दोनों ने अपने कुछ राजनयिकों को वापस बुला लिया। हालांकि ट्रूडो सरकार के सत्ता से बाहर होने और मार्क कार्नी के सत्ता संभालने के बाद से भारत कनाडा के रिश्तों में फिर से बेहतरी हो रही है। मार्क कार्नी भारत दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे का मकसद दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को फिर से मजबूत करना है। इसे कनाडा द्वारा व्यवहारिक विदेश नीति अपनाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। भारत आज दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है और बड़ा बाजार है। ऐसे समय में जब अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में तनाव है तो कनाडा चीन और भारत जैसे देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में जुटा है और भारत को लेकर उसके रुख में बदलाव को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

एपस्टीन फाइल्स पर बवालः ट्रंप से जुड़े आरोप के रिकॉर्ड रोके जाने की जांच करेगा अमेरिकी न्याय विभाग, बयान जारी

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका का न्याय विभाग यह समीक्षा कर रहा है कि क्या जेफरी एपस्टीन से जुड़े कुछ दस्तावेज गलती से सार्वजनिक होने से रोके गए। यह कदम तब उठाया गया, जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जारी रिकॉर्ड्स में डोनाल्ड

ट्रंप पर लगाए गए एक महिला के आरोपों से जुड़े सभी एफबीआई इंटरव्यू सारांश (समरी) शामिल नहीं थे। महिला ने आरोप लगाया था कि 1980 के दशक में नाबालिग होने के दौरान उसके साथ ट्रंप और एपस्टीन दोनों ने यौन शोषण किया था। ट्रंप इन आरोपों से लगातार इनकार करते रहे हैं। न्याय विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि घिसलेन मैक्सवेल के आपराधिक मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज गायब बताए जा रहे हैं और उनकी समीक्षा की जा रही है। यदि कोई रिकॉर्ड गलत तरीके से रोका गया पाया गया और वह कानून के तहत जारी किया जाना चाहिए, तो उसे प्रकाशित किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2019 में एफबीआई ने महिला से चार बार पूछताछ की थी, लेकिन सार्वजनिक फाइलों में सिर्फ एक इंटरव्यू का सारांश शामिल किया गया। इन लापता रिकॉर्डों की खबर सबसे पहले पत्रकार रोजर सोलेनबर्गर ने सबस्टैक और एनपीआर पर दी थी, और तब से द न्यूयॉर्क टाइम्स, एमएस नाउ और सीएनएन सहित अन्य समाचार संगठनों द्वारा भी इसका दस्तावेजीकरण किया गया है। प्रतिनिधि सभा की निगरानी समिति (हाउस ओवरसाइट कमेटी) के शीर्ष डेमोक्रेट सांसद रॉबर्ट गार्सिया ने एक बयान में कहा कि उनकी समिति रोके गए रिकॉर्ड की जांच करेगी। उन्होंने दावा किया कि न्याय विभाग ने संभवतः एफबीआई इंटरव्यू से जुड़े दस्तावेज गैरकानूनी रूप से रोके हैं।

जबरन कब्जे वाले इलाके खाली करो, पीओके पर भारत की पाकिस्तान को फटकार, सुनाई खरी–खरी

संयुक्त राष्ट, एजेंसी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र में पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए तगड़ी फटकार लगाई है। भारत ने इस्लामाबाद पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि जम्मू और कश्मीर का विकास पथ पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं के बिल्कुल विपरीत है। 23 फरवरी से 31 मार्च तक आयोजित हो रहे सत्र में 25 फरवरी को आयोजित उच्च स्तरीय सत्र के दौरान भारत के जवाब देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस समूह ने खुद को एक सदस्य देश के लिए श्प्रतिबिंब कक्षश के रूप में इस्तेमाल होने दिया है। अनुपमा सिंह ने कहा कि हम इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। साथ ही यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान का लगातार दुष्प्रचार ईर्ष्या से भरा हुआ है। सिंह ने भारत के उस चिरस्थायी रुख को दोहराया कि जम्मू और कश्मीर श्भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा।श उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, 1947 में इस क्षेत्र का भारत में विलय पूरी तरह से कानूनी और अपरिवर्तनीय था। उन्होंने कहा, श्इस क्षेत्र से संबंधित एकमात्र लंबित विवाद पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा है और उन्होंने इस्लामाबाद से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों को खाली करने को कहा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नियमित सत्र के उच्च स्तरीय खंड में, जिनेवा में प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा, श्पाकिस्तान और ओआईसी द्वारा उच्च स्तरीय खंड के दौरान उठाए गए मुद्दों के जवाब में भारत को अपने उत्तर देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए विवश होना पड़ा है। हम इन आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुष्प्रचार को दोहराकर, ओआईसी यह प्रकट करता है कि वह किस हद तक एक सदस्य देश के प्रभाव में आ गया है, और उस देश की राजनीतिक बाध्यताओं के लिए एक प्रतिध्वनि कक्ष बनकर रह गया है। पाकिस्तान का निरंतर दुष्प्रचार ईर्ष्या से भरा है। हम इसे महत्व नहीं देना चाहते, लेकिन तथ्यों के आधार पर इसका खंडन करने के लिए हम कुछ बिंदु उठाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की किसी भी प्रकार की मनगढ़ंत बयानबाजी या दुस्साहसी दुष्प्रचार इस अटल तथ्य को नहीं बदल सकता कि जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार पूरी तरह से कानूनी और अपरिवर्तनीय था। वास्तव में, एकमात्र लंबित मुद्दा यह पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा है। हम पाकिस्तान से जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करने का आह्वान करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में आम चुनाव और विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान इस बात का प्रमाण है कि वहां की जनता ने पाकिस्तान द्वारा प्रचारित आतंकवाद और हिंसा की विचारधारा को खारिज कर दिया है।

जिनेवा बैठक से पहले ट्रंप और जेलेंस्की ने फोन पर की बातचीत, इन मुद्दों पर किया गया मंथन

कीव, एजेंसी। जिनेवा में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने फोन पर विस्तार से चर्चा की। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने का रास्ता खोजना है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश पर इस बातचीत की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस कॉल में ट्रंप के साथ उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल थे। जेलेंस्की ने शांति बहाली की कोशिशों में ट्रंप और उनकी टीम की सक्रिय भागीदारी के लिए उनका आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने जिनेवा में होने वाली द्विपक्षीय बैठक के कार्यसूची पर चर्चा की। इसके साथ ही मार्च की शुरुआत में होने वाले त्रिपक्षीय सत्र की तैयारियों को लेकर भी बात हुई। जेलेंस्की ने कहा कि वे श्पीयूआरएलश पहल को बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यूक्रेन ने अमेरिका से जो एयर डिफेंस मिसाइलें खरीदी हैं, वे इस कठिन सर्दी में लोगों की जान बचाने और चुनौतियों का सामना करने में बहुत मददगार साबित हो रही हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति का मानना है कि इन बैठकों के माध्यम से बातचीत को शीर्ष नेताओं के स्तर तक ले जाने का मौका मिलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुश्किल और संवेदनशील मुद्दों को सुलझाने और युद्ध को पूरी तरह खत्म करने का यही एकमात्र प्रभावी तरीका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इन शांति प्रयासों का समर्थन किया है। इससे पहले मंगलवार को जेलेंस्की ने रूस के हमले के चार साल पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने केवल तीन दिनों में कीव पर कब्जा करने की कोशिश की थी,

प्रतापगढ़ ब्यूरो
शरद कुमार श्रीवास्तव
7/31, अचलपुर, प्रतापगढ़

बर्फ के गोले पर सियासत, पुलिस ने कहा– हम पर हमला हुआ, ममदानी बोले– बच्चों की शरारत

न्यूयॉर्क, एजेंसी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भारी बर्फबारी के बाद सोमवार को वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में बड़ी संख्या में लोग स्नोबॉल फाइट (बर्फ के गोले फेंकने का खेल) के लिए जमा हुए। माहौल शुरू में मस्ती भरा था, लेकिन धीरे–धीरे हालात बिगड़ गए।

सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो में दिखा कि जब पुलिस के दो अधिकारी पार्क के अंदर पहुंचे तो कई लोगों ने चारों तरफ से उन पर बर्फ के गोले फेंकने शुरू कर दिए। कुछ वीडियो में दिख रहा है कि एक अधिकारी की आंख लाल हो गई थी और वह आंख मलते नजर आया।

संस्थापक
स्व.कन्हैया लाल
स्व.श्रीमती साधना
सम्पादक
उमेश चंद्र श्रीवास्तव
प्रबन्ध सम्पादक
अरविन्द पाण्डेय
संयुक्त सम्पादक
अनंत श्रीवास्तव
संयुक्त सम्पादक (तकनीकी)
केशव श्रीवास्तव
विधि सलाहकार
कल्पना श्रीवास्तव

शहर समता

स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक उमेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कम्पीटेन्ट बिजनेस सर्विसेज, विष्णु पदम कुटीर 115डी/2ई लूकरगंज, इलाहाबाद से मुद्रित कराकर 289/238ए,कर्नलगंज इलाहाबाद से प्रकाशित

सम्पादक
उमेश चन्द्र श्रीवास्तव
मो.नं.9005239332

आर.एन.आई.नं.
यूपीएचआईएन/2004/22466

Email : shaharsamta@gmail.com

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के अधीन ही होंगे।